A Daily News Magazine
इंदौर
शनिवार, 28 फरवरी, 2026

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 148, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

सौंदला गांव : अलग कुओं की परंपरा से साझा थाली तक का सफर'

पूर्वा चिटणीस

महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सौंदला में शाम ढलते ही, एक जवान औरत अपने घर से चाय की ट्रे लेकर बाहर निकलती है और अपने बरामदे पर जमा हुए गांव के सरपंच समेत कुछ आदमियों को चाय के कप देती है। आदमी गर्म चाय पीते हैं, मुस्कुराते हैं और औरत को धन्यवाद देते हैं।

ग्रामीण महाराष्ट्र में यह एक सामान्य सा दृश्य है। लेकिन कुछ साल पहले तक वहां बैठे ये सभी 'ऊंची जाति' के पुरुष उस घर की देहलीज पार नहीं करते थे। अहिल्यानगर जिले के इस गांव में, जहां कभी जाति चुपचाप दूरी तय करती थी, वहां साथ बैठकर चाय पीना बराबरी का एक छोटा लेकिन बड़ा कदम बन गया है।

सौंदला ने एक साहसिक कदम उठाया है। 5 फरवरी को ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें गांव को 'जाति-मुक्त' घोषित किया गया। इस घोषणा में किसी से उसकी जाति पूछने पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक जीवन बिना ऊंच-नीच के साझा करने और इंसानियत की भाषा बोलने पर जोर दिया गया है।

इस बदलाव की झलक छोटे-छोटे इशारों में दिखती है। दलित परिवार के घर पर साथ बैठकर चाय पीना. बच्चों का बिना किसी पुरानी सीमा के साथ खेलना। त्योहारों का अलग-अलग नहीं, बल्कि मिलकर मनाया जाना।

यह प्रस्ताव राजधानी मुंबई से करीब 350 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के सरपंच द्वारा बुलाई गई विशेष ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पास किया गया। यह जिला पहले ध्रुवीकरण और सामाजिक बहिष्कार की खबरों के लिए सुर्खियों में रहा है। सौंदला के सरपंच शरद शरद अर्गडे ने कहा कि पड़ोसी इलाकों और पूरे महाराष्ट्र में हाल के वर्षों में बढ़ते जातीय और सांप्रदायिक तनाव ने उन्हें जल्दी कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। हम गाय को मां मानते हैं, लेकिन अपने ही जैसे इंसानों को इंसान मानने से इनकार कर देते हैं। इसे बदलने की जरूरत है। लोग एक खास जाति के व्यक्ति से सामान खरीदने से मना कर रहे हैं। कुछ जगहों पर लोग निचली जाति के डॉक्टर से इलाज कराने से भी मना कर रहे हैं। यह सोच मेरे गांव में भी जड़ न जमा ले, इससे पहले मैं डरने लगा था। इसलिए मैंने कदम उठाने का फैसला किया।'

ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावलों की तस्वीरें लगी हैं। अर्गडे ने कहा कि इसका मकसद शिवाजी के धर्मनिरपेक्ष स्वभाव को दिखाना है और यह बताना है कि उन्होंने अपने मावलों में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। अर्गडे के अनुसार, 'जाति-मुक्त गांव' का विचार उन्हें एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद झिंजाडे ने सुझाया था। साथ ही उनके पिता का प्रभाव और उनकी पत्नी के प्रयासों ने भी सोच बदलने में भूमिका निभाई। सौंदला ने खुद को केवल जाति-मुक्त घोषित नहीं किया है, बल्कि ग्रामीणों ने अन्य सुधार भी किए हैं। जैसे गांव को गाली-गलौज और अपमानजनक शब्दों से मुक्त बनाना। विधवा विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

पड़ोसी बीड जिले का उदाहरण देते हुए, जहां इस समय मराठा और ओबीसी के बीच खुला तनाव चल रहा है, अर्गडे ने कहा, 'आज हमारे राज्य में जो हो रहा है, वह बहुत चिंताजनक है। लोग बंट रहे हैं और दंगे हो रहे हैं। भविष्य में ऐसा लग रहा है कि हमें पाकिस्तान से नहीं, बल्कि एक-दूसरे से लड़ना पड़ेगा।' अहिल्यानगर जिला, जिसे 2023 तक अहमदनगर कहा जाता था, पिछले दो वर्षों से कई गांवों में ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को लेकर खबरों में रहा है। नफरत भरे भाषण, मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की अपील, और धार्मिक ढांचों को लेकर विवाद की खबरें आम रही हैं।

सौंदला की आबादी लगभग 2,500 है और यहां करीब 450 परिवार रहते हैं। ग्रामीणों के अनुसार, लगभग 70 प्रतिशत निवासी 'ऊंची जाति' से हैं और बाकी दलित हैं। करीब 4 परिवार मुस्लिम समुदाय से हैं, जबकि 10 से 15 परिवार ईसाई धर्म मानते हैं। 5 फरवरी का प्रस्ताव अचानक नहीं आया. ग्रामीणों का कहना है कि अर्गडे और उनकी पत्नी प्रियंका, जो पूर्व सरपंच रह चुकी हैं, ने धीरे-धीरे इसके लिए जमीन तैयार की।

अर्गडे 2003 से स्थानीय राजनीति में सक्रिय हैं। उनके पिता बाबा अर्गडे गांव में अनुभवी कम्युनिस्ट नेता थे। जब अर्गडे पहली बार 2003 में सरपंच बने, जो कि अब उनका तीसरा कार्यकाल है, तब उन्होंने गांव में प्रगतिशील विचार लागू करने शुरू किए। शुरुआत में यह चुनौतीपूर्ण था, लेकिन समय के साथ सोच बदलने लगी, उन्होंने कहा। प्रियंका ने कहा शुरुआत में मैं भी निचली जाति के लोगों के घर के अंदर जाने को लेकर संकोच में थी. मैं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने उनके घर पानी पी लिया। मैं हिचकिचाती थी। बदलाव की शुरुआत घर से होती है।'

समय के साथ लोग एक-दूसरे के करीब आने लगे। दूरियां कम होने लगीं। जाति-मुक्त प्रस्ताव से दो महीने पहले गांव ने एक और प्रतीकात्मक प्रस्ताव पास किया था। इसमें तय हुआ कि हर सुबह करीब 10 बजे मंदिर के ऊपर लगे लाउडस्पीकर से राष्ट्रगान बजाया जाएगा। लोग अपने खेतों में काम करते हुए भी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने लगे। अर्गडे ने कहा, 'ऐसा करके मैं लोगों को बताना चाहता था कि हम पहले भारतीय हैं। हम सिर्फ अपने देश के बेटे हैं, जाति के आधार पर बंटे हुए नहीं। 'पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान, मंदिर, श्मशान घाट, पानी के स्रोत, स्कूल, कार्यक्रम और सरकारी सेवाएं सभी के लिए बराबर रूप से उपलब्ध होंगी। जाति या धर्म से जुड़े बयानों, धार्मिक बहिष्कार या जाति के आधार पर अन्याय को लेकर किसी तरह का सांप्रदायिक तनाव नहीं होना चाहिए। गांव का कोई भी सदस्य सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट साझा नहीं करेगा। अगर ऐसा करते पकड़ा गया तो सजा दी जाएगी। कई ग्रामीणों के मुताबिक सौंदला में खुला भेदभाव पहले ही कम हो चुका था। लेकिन बुजुर्गों को एक अलग समय याद है। 5 फरवरी के प्रस्ताव के बाद से ग्रामीण दो त्योहार साथ मना चुके हैं, जिनमें शिव जयंती भी शामिल है। जाति-मुक्त घोषणा सौंदला का पहला सामूहिक सुधार नहीं है। ग्रामीणों ने गाली-गलौज पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी पास किया है। एक साल पहले गांव ने भेदभावपूर्ण विधवा प्रथाओं को औपचारिक रूप से हतोत्साहित किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन शुरू किया। एक अलग पहल के तहत गांव में छात्रों के लिए रोज दो घंटे का 'नो मोबाइल' समय अनिवार्य किया गया है। अर्गडे ने कहा, 'बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी सावधानी बरती जाए।'

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

उमंग और सामाजिक स्नेह का जीवंत महोत्सव है भगोरिया पर्व : मुख्यमंत्री

- मुख्यमंत्री आलीराजपुर जिले के उदयगढ़ के स्थानीय भगोरिया पर्व में हुए शामिल

पारंपरिक वेषभूषा, आभूषण और मांदल की थाप में रचा-बसा भगोरिया उत्सव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि फाल्गुन मास के रंगों, मांदल की थाप और जीवन-प्रेम की उमंग से सराबोर भगोरिया पर्व जनजातीय संस्कृति, सामाजिक स्नेह और परंपरागत जीवन मूल्यों का जीवंत उत्सव है। इसको प्रत्यक्ष रूप से भगोरिया पर्व में शामिल होकर जिया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अलीराजपुर के उदयगढ़ भगोरिया पर्व स्थल पर पारंपरिक लोकधुनों, नृत्य और उल्लासपूर्ण वातावरण ने सम्पूर्ण क्षेत्र को सांस्कृतिक रंगों से भर दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगोरिया पर्व जनजातीय संस्कृति, प्रेम और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। मध्यप्रदेश सरकार जनजातीय परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। विरासत को विकास की राह पर ले जाने के संकल्प के साथ इस उल्लासमय पर्व को गरिमा और भव्यता के साथ मनाया गया। यह आयोजन जनजातीय संस्कृति की सशक्त पहचान और राज्य सरकार की संवेदनशील सोच को प्रतिबिंबित करता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का जनजातीय समाज एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मंत्री जनजातीय संस्कृति के प्रतीक तीर कमान भेंट किया। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पुष्प-गुच्छ से स्वागत किया गया। मंत्री श्री द्वारा मंच से सभी को राष्ट्रीय पर्व भगोरिया की शुभकामनाएं दी। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह ने कहा कि आलीराजपुर जिले के उदयगढ़ में आयोजित स्थानीय भगोरिया पर्व में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सहभागिता से उत्सव का उल्लास और अधिक बढ़ गया।

भगोरिया उत्सव में जनजातीय युवक-युवतियां रंग-बिरंगी पारंपरिक वेषभूषा में सजे-धजे दिखाई दिए। पुरुष वर्ग पारंपरिक धोती, अंगोछा एवं साफा धारण किए हुए थे, जबकि महिलाएं कांचली, घाघरा, ओढ़नी तथा पारंपरिक कढ़ाईयुक्त परिधानों में सुसज्जित रहीं। चांदी के हार, हांसली, कड़े, पायल, बिछिया एवं अन्य पारंपरिक आभूषणों की झंकार ने पर्व को भव्यता प्रदान की। मांदल, ढोल एवं अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर कुर्ता कुर्राटियों के साथ लोकनृत्य करते जनजातीय समाज, सामूहिक उल्लास और आपसी मेल-जोल ने भगोरिया के माहौल को जीवंत एवं स्मरणीय बना दिया।

मामेरा रस्म के दौरान दूल्हे की मां को हार्ट अटैक

- भाई की याद में भतीजे को गले लगा कर रोईं और थम गईं सांसें, बीपी की दवा लेना भूल गई थीं

झाबुआ (नप्र)। झाबुआ के सारंगी में मामेरा रस्म के दौरान दूल्हे की मां को दिल का दौरा पड़ गया। कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। मृतका की पहचान गायत्री पाटीदार के रूप में हुई है। दरअसल, महिला के बेटे गोलू की शादी बुधवार 25 फरवरी को थी। बारात बरवेट गांव से दुल्हन लेकर लौट आई थी। गुरुवार को रिसेप्शन (स्वागत समारोह) रखा गया था। सुबह के भोज के बाद दोपहर में मायरा कार्यक्रम था। इसी दौरान गायत्री के मायके वाले मामेरा की रस्म के लिए पहुंचे। परंपरा के मुताबिक, गायत्री अपने मायके वालों का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ीं। गायत्री का एक ही भाई था। कई साल पहले गंभीर बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। मामेरा की रस्म के लिए जब भतीजा पहुंचा था, तो उसे देखकर वह भावुक हो गईं।वे भतीजे को गले लगाकर रोने लगीं। उनका बीपी लो रहता था। शादी की व्यस्तता के कारण वह दवा लेना भूल गई थीं। ज्यादा रोने और मानसिक तनाव के कारण उनका ब्लडप्रेशर गिर गया।

गायत्री पाटीदार, मृतका

मामेरा की चुनरी अर्थी पर ओढ़ाई

ब्लडप्रेशर में अचानक गिरावट के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा। विवाह के खुशी के माहौल में अचानक चीख-पुकार मच गई। अचानक तबीयत बिगड़ने पर गायत्री को परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि, जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

शरद की सुबह

वस्तुतः

मैं जो हूँ
मुझे वहीं रहना चाहिए
यानी
वन का वृक्ष
खेत की मेड़
नदी की लहर
दूर का गीत
व्यतीत
वर्तमान में
उपस्थित भविष्य में
मैं जो हूँ मुझे वहीं रहना
चाहिए
तेज गर्मी
मूसलाधार वर्षा
कड़ाके की सर्दी
खून की लाली
दूब का हरापन
फूल की जर्दी
मैं जो हूँ
मुझे अपना होना
ठीक ठीक सहना चाहिए
तपना चाहिए
अगर लोहा हूँ
हल बनने के लिए
बीज हूँ
तो गड़ना चाहिए
फल बनने के लिए
मैं जो हूँ
मुझे वह बनना चाहिए
धारा हूँ अन्त : सलिला
तो मुझे कुएँ के रूप में
खनना चाहिए
ठीक जरूरतमंद हाथों से
गान फैलाना चाहिए मुझे
अगर मैं आसमान हूँ
मगर मैं
कब से ऐसा नहीं
कर रहा हूँ
जो हूँ
वही होने से डर रहा हूँ।

- भवानी प्रसाद मिश्र

दिल्ली शराब नीति केस में कोर्ट ने

केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी किया

कोर्ट बोला- चार्जशीट में खामियां, फैसले के बाद केजरीवाल रोते हुए बोले- जिंदगीभर ईमानदारी कमाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। शराब घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कहा- दोनों के खिलाफ बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता है। इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया।

हमारे खिलाफ साजिश...

मोदी, शाह, राहुल गांधी का नाम लेकर अरविंद केजरीवाल ने जमकर साधा निशाना- कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ने हमारे खिलाफ साजिश रची। हम कट्टर ईमानदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी और प्रतिष्ठा अर्जित की और मोदी- शाह इसे धूमिल करना चाहते थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो दिल्ली में दोबारा चुनाव कराएं। आज चुनाव हुए दिल्ली में 10 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी।

बरी होने पर अन्ना हजारे ने कहा मुझे खुशी हुई- दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों बरी पर अन्ना हजारे ने भी खुशी जताई है। अन्ना हजारे ने कहा, हमारा देश अपनी न्यायिक और सुरक्षा प्रणालियों की ताकत पर चलता है

टीएमसी ने केंद्रीय एजेंसियों के 'दुरुपयोग' के लिए बीजेपी को आड़े हाथों लिया- तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में बरी करने के फैसले का स्वागत किया और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया।

- **स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाया-** स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने इस केस का फैसला सुनाया। वे दिल्ली कोर्ट के एक अनुभवी जज हैं। वे दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस के एक सीनियर न्यायिक अधिकारी हैं। अभी वे नई दिल्ली के राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्पेशल जज (पीसी एक्ट) सीबीआई-01 के पद पर तैनात हैं।
- **दिल्ली शराब नीति केस में यह 23 लोग बरी हुए-** अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के. कविता, दुर्गेश पाठक, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिल्लई, मूथा गौतम, समीर महेंद्रू, अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे, बुचिबाबू गोरंतला, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद कुमार सिंह, चनप्रीत सिंह, अमित अरोरा, विनोद चौहान, आशीष चंद माथुर, शरत रेड्डी।

कांग्रेस विधायक ने किया

विधानसभा में शीर्षासन

- हर्ष फायरिंग पर एफआईआर को लेकर जताया विरोध, सदन से कांग्रेस ने किया वॉकआउट
- बोले- पटाखा भी फोड़ूं तो केस

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को नजारा कुछ ऐसा था कि हर कोई दंग रह गया। कार्यवाही चल रही थी और इसी बीच श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू लाल जंडेल अचानक सिर के बल खड़े हो गए। सदन के भीतर विधायक जी का यह शीर्षासन देखकर सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के माथे पर बल पड़ गए। जंडेल का आरोप है कि सरकार और पुलिस मिलकर उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमों के जाल में फंसा रही है।

एक महीने में 3 केस, अब तक 15 मामले- बाबू जंडेल का कहना है कि पिछले एक महीने में ही उनके खिलाफ तीन नई एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं, जिससे उनके ऊपर दर्ज केसों की कुल गिनती 15 तक पहुंच गई है। विधायक ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी के नेता खुलेआम फायरिंग करते हैं, नाचते-गाते हैं, उन पर कोई आंच नहीं आती। लेकिन जब मैं शिव बारात में एक पटाखा फोड़ देता हूं, तो पुलिस तुरंत केस ठोक देती है। उनका दावा है कि वे जनता और किसानों की आवाज उठाते हैं, इसलिए सरकार उन्हें निशाना बना रही है।

मर जाऊंगा, पर डरूंगा नहीं- उग्र अंदाज में विधायक जंडेल ने साफ कह दिया कि वो जेल जाने या गोली खाने से नहीं डरते। गांधी प्रतिमा को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आज गांधी जी होते, तो ये अन्याय देखकर रो पड़ते। जंडेल ने चेतावनी दी है कि अगर ये फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए गए, तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शनिवार, 28 फरवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

कोलकाता सहित बंगाल के कई जिलों में भूकंप, 5.4 तीव्रता

- तेज झटके महसूस हुए, इमारतें हिलीं, लोग सड़कों पर निकले

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित कई जिलों में शुक्रवार दोपहर करीब 1.30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के ढाका स्थित अगरगांव में था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई। पश्चिम बंगाल से अगरगांव की दूरी लगभग

26 किलोमीटर बताई जा रही है। झटके इतने तेज थे कि कोलकाता में बहुमंजिला इमारतें कुछ सेकेंड तक हिलती रहीं। अचानक कंपन महसूस होते ही लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए।

एआईएडीएमके से निष्कासित तमिलनाडु के पूर्व सीएम पन्नीरसेल्वम डीएमके में शामिल

मुख्यमंत्री स्टालिन ने सदस्यता दिलाई

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व एआईएडीएमके नेता ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) ने शुक्रवार को डीएमके का दामन थाम लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में पार्टी जॉइन की। यह कदम अप्रैल-मई में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले उठाया

गया है। ओपीएस तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे दिवंगत नेता जे जयललिता के करीबी माने जाते थे।

2 दिन के इजराइल दौरे से लौटे पीएम मोदी

- दोनों देशों के बीच 27 एमओयू और एग्रीमेंट हुए

नईदिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज़राइल के ऐतिहासिक दो दिन के स्टेट विज़िट के बाद शुक्रवार रात 1 बजे भारत लौट आए। यह नौ साल में उनका पहला विजिट था। इस दौरान दोनों देशों ने अपने आपसी रिश्तों को एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया। अलग-अलग सेक्टर में 27 एमओयू और एग्रीमेंट पर साइन हुए।

बंगाल में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन हाई कोर्ट से मिली 'परिवर्तन यात्रा' की सशर्त अनुमति ; शाह दिखाएंगे हरी झंडी

कोलकाता (एजेंसी)। बंगाल में भाजपा की प्रस्तावित 'परिवर्तन यात्रा' को लेकर चल रही कानूनी रस्साकशी के बीच कोलकाता हाई कोर्ट ने सशर्त अनुमति दे दी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की पीठ में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि एक और दो मार्च को दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक यात्रा निकाली जा सकेगी, लेकिन किसी भी स्थान पर एक हजार से अधिक लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में जंग

इस्लामाबाद पर हमला.., तालिबान लड़ाकों ने कहर मचा दिया !

- पाक बोला- 133 अफगान लड़ाके मारे ,तालिबान के समर्थन में भारत
- परमाणु ठिकाने और पीएम हाउस तक पहुंचे तालिबान ड्रोन
- पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने युद्ध की औपचारिक घोषणा की

काबुल/इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की औपचारिक घोषणा कर दी है। लेकिन इस पर भी खुद उन्हीं को मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में घुसकर भीषण हमला कर डाला है। इस्लामाबाद में मौजूद पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर ड्रोन से हमला किया गया। इस ड्रोन हमले में बम से अटैक किया गया। उसमें हुए नुकसान की अभी जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन इससे कम से कम पाकिस्तान की पोल खुल गई, जो चीन से मिले अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ा गुमान किया करता था।

पाकिस्तानी सेना तालिबान के हाथों बुरी तरह से पिटती हुई नजर आ रही है।पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात जंग जैसे हो गए हैं।

55 पाकिस्तानी सैनिकों को किया ढेर

टोलो न्यूज के मुताबिक तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 'गजब लिल हक' नाम का ऑपरेशन शुरू किया और काबुल समेत कई प्रांतों में हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि उसके हमलों में 274 अफगान लड़ाके मारे गए, जबकि 400 से ज्यादा घायल हैं। दोनों तरफ से करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। भारत ने भी पाकिस्तान के हमलों की निंदा करते हुए अफगानिस्तान का समर्थन किया है। गुरुवार रात से पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर झड़पें शुरू हुई हैं, जब तालिबान ने पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों पर जवाबी हमले किए। इसके बाद दोनों पक्षों में फायरिंग हुई और काबुल की ओर से ड्रोन हमला किया गया।

- **तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी जेट गिराया, 19 चौकियों पर कब्जा-** अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी लड़ाकों ने एक पाकिस्तानी जेट भी मार गिराया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अफगान सरकार का दावा है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव उसके पास हैं। पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वॉर्टर और 19 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है।
- **अफगानिस्तान आर्मी पाकिस्तान सेना को दे रही है कड़ी चुनौती -** अफगानिस्तान ने कथित तौर पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया है। गुरुवार शाम को बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ने के बाद अफगानिस्तान की ओर से शुक्रवार को ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के अंदर हमले किए गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी ऑफिसर आदिल राजा का दावा है कि अफगानिस्तान से आए ड्रोन ने इस्लामाबाद के पास पाकिस्तानी मिलिट्री शासन के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। पाकिस्तानी आर्मी के आलोचक और ब्रिटेन में निर्वासन में रह रहे आदिल राजा का कहना है कि अफगानिस्तान से लॉन्च किए गए ड्रोन ने पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर उसके प्रमुख शहरों पर हमले किए हैं। राजा का कहना है कि तालिबान के ड्रोन जमरूद मिलिट्री बेस, नौशेरा किला, स्वाबी में पुलिस स्टेशन और इस्लामाबाद के पास एक न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर तक पहुंचे हैं।

राजपुर में बड़ा बस हादसा

हाईवे से फिसलकर खेत में घुसी यात्री बस, 14 घायल

बड़वानी (नप्र)। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के राजपुर में शुक्रवार को एक बड़ा यात्री बस हादसा सामने आया, जब खंडवा से बड़वानी जा रही एक निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे खेत में जा घुसी। इस हादसे में 14 यात्री घायल हो गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो घटना को स्पष्ट कर रहा है। राजपुर थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया ने बताया कि खंडवा-वडोदरा हाईवे पर एक पेट्रोल पंप के पास यह दुर्घटना हुई। बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और सीधे खेत में जा घुसी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका।

भयावह था सीन, दौड़कर पहुंचे लोग यात्रियों को

निकाला- हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े और पुलिस के साथ मिलकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस जिस रफ्तार से नीचे उतरी, वह दृश्य बेहद भयावह था। थाना प्रभारी ने भी स्वीकार करते हुए कहा कि गनीमत रही कि बस सड़क और खेत के बीच लगे पेड़ से नहीं टकराई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

यात्रियों को फ्रैक्चर आए हैं, 9 रेफर- सभी 14 घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर पहुंचाया गया। बीएमओ डॉ. देवेंद्र रोमड़े के अनुसार, कुछ यात्रियों में फ्रैक्चर की आशंका को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद 9 घायलों को जिला अस्पताल बड़वानी रेफर किया गया है।

नवोन्मेष 2026: 12 से 15 मार्च तक होगा आयोजन

भोपाल। मध्य भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में इनोवेशन कार्निवाल 'नवोन्मेष 2026' का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता, रचनात्मकता और प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को बढ़ावा देना है। यह अटल इन्क्यूबेशन सेंटर-रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी (एआईसी-आरएनटीयू) द्वारा स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी और रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 10 हजार से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें छात्र, स्टार्टअप, बिजनेस लीडर्स, निवेशक और नीति निर्माता और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े सभी लोग शामिल होंगे। प्रतिभागियों के लिए इसमें 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार जीतने का मौका होगा।

नवोन्मेष 2025 प्रतिभागियों को उद्योग विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों, निवेशकों और स्टार्टअप सलाहकारों से संपर्क करने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे उन्हें निरंतर विकसित हो रहे व्यवसाय और प्रौद्योगिकी परिदृश्य में मूल्यवान जानकारी प्राप्त हो सके। पैनल चर्चाओं, व्यावहारिक कार्यशालाओं और मेंटरशिप कार्यक्रमों के माध्यम से नवोन्मेष 2026 उपस्थित लोगों को उनके विचारों और उपक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान, कौशल और संसाधनों से लैस करेगा। है। अधिक जानकारी और रजिस्ट्रेशन के लिए, पर जाएँ। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च हैद्य

स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा कि नवोन्मेष 2026 केवल एक छात्र उत्सव नहीं, बल्कि युवाओं की रचनात्मक क्षमता, उद्यमिता और तकनीकी नवाचार को वास्तविक अवसरों से जोड़ने वाला एक सशक्त मंच है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने पहली बार कॉम्बैट हेलिकॉप्टर की उड़ान भरी

जैसलमेर (एजेंसी)। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज (जैसलमेर) में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 'वायु शक्ति-2026' शुरू हुआ। राष्ट्रपति ने जैसलमेर की सीमावर्ती एयरस्पेस में पहली बार किसी लड़ाकू हेलिकॉप्टर को को-पायलट

किया। राष्ट्रपति पोखरण रेंज पहुंची, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में 'वायु शक्ति' युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई। मुर्मू 26 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंची हैं।

वायु शक्ति-2026 में प्रचंड के अलावा राफेल, सुखोई-30 एमकेआई और अपाचे जैसे विमानों ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया।

राफेल: एक डबल इंजन वाला मल्टीरोल फाइटर एयर क्राफ्ट है। ये हवा से हवा, हवा से जमीनी हमले कर सकता है।

सुखोई: सुखोई एसयू-30 एमकेआई दो इंजन वाला लड़ाकू विमान है जिसे भारतीय वायु सेना के लिए रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो और भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है।

मधुबनी मेडिकल कॉलेज का फरमान

रमजान में साथ दिखे छात्र-छात्रा तो करा दिया जाएगा निकाह

मधुबनी (एजेंसी)। बिहार के मधुबनी मेडिकल कॉलेज का एक अजीबोगरीब और विवादित सर्कुलर इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कॉलेज प्रशासन ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर छात्र-छात्राओं के साथ खड़े होने पर न केवल पाबंदी लगाई है, बल्कि उल्लंघन करने पर सीधे निकाह करा देने की चेतावनी दी है। इस तुगलकी फरमान के सामने आने के बाद संस्थान के छात्र-छात्राओं में हड़कंप मचा हुआ है।

मधुबनी मेडिकल कॉलेज के सर्कुलर में दी गई निकाह की चेतावनी- मिली जानकारी के अनुसार, मधुबनी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के हस्ताक्षर और मुहर के साथ जारी इस पत्र में रमजान के महीने का हवाला दिया गया है। सर्कुलर में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि रमजान के पाक महीने के दौरान कोई भी लड़का और लड़की (कपल)

शंकराचार्य की अर्जी पर फैसला सुरक्षित गिरफ्तारी पर रोक, पुलिस को पूछताछ की छूट

इलाहाबाद (एजेंसी)। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अपने चेंबर में केस से जुड़े वकीलों को बताया कि अगली सुनवाई तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद, दोनों की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।

अदालत का विस्तृत आदेश रात तक हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो सकता है। इसी आदेश में यह भी उल्लेख होगा कि मार्च के तीसरे सप्ताह में अगली सुनवाई किस तारीख को होगी। तब तक दोनों आरोपियों के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, हालांकि पुलिस चाहे तो पूछताछ कर सकती है और शंकराचार्य को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। जस्टिस जे.के. सिन्हा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं की भारी भीड़ और गहमागहमी के कारण सुनवाई चेंबर में की गई, जहां केवल केस से जुड़े वकील मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने बचाव पक्ष से यह भी पूछा कि पहले सेशन कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया गया और सीधे हाईकोर्ट आने का औचित्य क्या है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने मुख्य रूप से अग्रिम जमानत अर्जी की पोषणीयता पर आपत्ति जताई।

यह रोड मुसलमान के लिए नहीं है, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर 'हिंदू रक्षा दल' ने लिखी विवादित बात

नईदिल्ली (एजेंसी)। देहरादून एक्सप्रेस-वे पर लिखे गए एक आपत्तिजनक स्लोगन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हाईवे की दीवारों और फ्लाईओवर पर मुस्लिम समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी हुई दिखाई दे रही है। स्लोगन में लिखा गया है, 'यह रोड मुसलमान के लिए नहीं है।' इस मामले ने क्षेत्र में संवेदनशीलता बढ़ा दी है और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

प्रशासन ने दीवार से हटाए आपत्तिजनक शब्द

मीडिया टीम ने वायरल वीडियो की सत्यता की जांच के लिए मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। हालांकि दीवारों पर लिखे गए शब्दों को बाद में मिटा दिया गया है, लेकिन उनके निशान अभी भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।

हिंदू रक्षा दल ने ली जिम्मेदारी

इस पूरे मामले में हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी ली है। संगठन के कुछ सदस्यों का दावा है कि उनकी महिला विंग ने यह नारे लिखे थे।

दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई

हमीरपुर (एजेंसी)। आजकल सोशल मीडिया पर आए दिन तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। कुछ वीडियो लोगों को हंसा देते हैं, तो कुछ हैरान कर देते हैं। कई बार ऐसे वीडियो भी सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर सच क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इस वीडियो को लेकर तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं और लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं।

बताया जा रहा है कि यह मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ थाना क्षेत्र का है। वीडियो में शादी के बाद की एक घटना दिखाई दे रही है, जहां परिवार के

लोग एक कमरे में बैठे नजर आ रहे हैं। माहौल सामान्य नहीं दिख रहा, बल्कि बहस और तनाव का माहौल दिखाई देता है। इसी दौरान सास और नई दुल्हन के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है, जो धीरे-धीरे झगड़े में बदल जाती है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कमरे में कई रिश्तेदार मौजूद हैं। नई नवेली दुल्हन और उसकी सास आमने-सामने बैठी हैं। बातचीत के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। दावा किया जा रहा है कि दुल्हन ने सुहागरात मनाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह कमरे में नहीं जाएगी।

मेरा प्रेमी आना वाला है...

कथित तौर पर दुल्हन ने यह भी कहा कि उसका प्रेमी आने वाला है और वह उसके साथ जाना चाहती है. यह बात सुनकर माहौल और ज्यादा गरम हो गया. इसके बाद सास गुस्से में आ गई और उसने दुल्हन को मारना-पीटना शुरू कर दिया।

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो के साथ लिखा गया है कि सुहागरात के दिन दुल्हन ने कमरे में जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसका प्रेमी आ रहा है, वह उसके साथ जाएगी। इसके बाद सास ने मौके पर ही उसकी पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग दुल्हन के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोग सास की गई मारपीट की आलोचना कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि चाहे मामला कुछ भी हो, किसी को भी हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। वहीं कुछ लोग इसे परिवार की निजी बात बता रहे हैं।

निगम ने बड़े बकायादारों की लिस्ट लगाई

इंदौर। नगर निगम ने ढोल बजाकर राजवाड़ा पर बड़े 57 बकायादारों की सूची लगाई। पोस्टर पर बकायादारों के नाम और कितनी राशि बकाया है यह जानकारी भी बताई गई। नगर निगम की टीम पोस्टर लेकर राजवाड़ा पहुंची। यहां पर पोस्टर लगाने के साथ ही ढोल भी बजाया गया। जोन 3 के एआरओ अनिल निकम ने बताया कि गत लोक अदालत में भी वार्ड 56, 57, 58 में बड़े बकायादारों की सूची की लिस्ट राजवाड़ा पर लगाई गई थी। उसका भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। पिछली लोक अदालत में 100 करोड़ से ज्यादा का राजस्व आया था। इस बार भी जो बड़े बकायादार है, जिन्हें कई बार उन्हें समझाइश दे चुके हैं, नोटिस जारी किए जा चुके हैं कि बकाया राशि जमा करा दें, लेकिन उन्होंने राशि जमा नहीं कराई है, इसलिए उनके नामों की सूची सार्वजनिक करते हुए राजवाड़ा और जोनल ऑफिस पर लगाई है। 14 मार्च को लोक अदालत है, इसलिए करदाताओं से अपील की है कि बकाया राशि लोक अदालत में जमा करा कर सरचार्ज में छूट का लाभ लें। लिस्ट में 57 लोगों के नाम हैं और 2 करोड़ रुपए की बकाया राशि बाकी है।

3500 से अधिक हेलमेट वितरित किए

इंदौर। सड़क सुरक्षा को लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाया जा रहा 'हेलमेट पहनें-सुरक्षित रहें' अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में अब तक 21 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर 3500 से अधिक हेलमेट जरूरतमंद वाहन चालकों को वितरित किए जा चुके हैं। पलासिया चौराहे पर विशेष आयोजन गुरुवार को पलासिया चौराहे पर आयोजित 21वें वृहद अभियान में पुलिस उपायुक्त (यातायात) राजेश कुमार त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के चालान बनाए गए और उन्हें सड़क सुरक्षा का महत्व समझाते हुए हेलमेट भी प्रदान किए गए। जो दोपहिया चालक स्वेच्छा से हेलमेट लगाए मिले, उनका अधिकारियों ने सम्मान कर उत्साहवर्धन किया। साथ ही नो पार्किंग और यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने वाले पोस्टरों का अनावरण किया गया, जिनमें ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी सुरक्षित यातायात के लिए प्रेरित करें।

40 साल पुराना खतरनाक मकान जमींदोज

इंदौर। होली पर्व को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने शहर में खतरनाक भवनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सोमवार सुबह राज मोहल्ला क्षेत्र में स्थित एक जर्जर मकान को तोड़कर जमींदोज कर दिया गया। पहले ही घोषित किया गया था खतरनाक ओल्ड राज मोहल्ला में गोपाल मिश्रा का करीब 40 वर्ष पुराना जी+1 मकान लंबे समय से खस्ताहाल स्थिति में था। नगर निगम को इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थीं। निरीक्षण के बाद भवन को पहले ही खतरनाक घोषित कर मकान मालिक को नोटिस जारी कर दिया गया था। निगम अधिकारियों के अनुसार मकान मालिक द्वारा चेतावनी के बावजूद भवन के खतरनाक हिस्से को नहीं हटाया गया। इसके चलते निगम की रिमूवल गैंग को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करनी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि होली से पहले सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अन्य खतरनाक मकानों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।

गर्मियों से पहले जल प्रबंधन पर फोकस

इंदौर। आगामी गर्मियों को देखते हुए शहर में जल प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गुरुवार तड़के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मुसखेड़ी स्थित जल वितरण प्रणाली स्काडा सेंटर पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान जल कार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा 'बबलू' एवं अपर आयुक्त आशीष पाठक भी मौजूद रहे। महापौर ने शहर की सभी टंकियों और जल वितरण प्रणाली को रियल टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से परखा तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मियों में किसी भी क्षेत्र में पानी की कमी न हो। उन्होंने बताया कि हाल ही में दो दिवसीय शटडाउन लेकर पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए, जिससे 10 एमएलडी पानी की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि एक अन्य फेज की मरम्मत जारी है,जो एक माह में पूर्ण होगी। इसके बाद 10 एमएलडी और बढ़ेगा। कुल 20 एमएलडी अतिरिक्त जल से गर्मियों में शहरवासियों को राहत मिलेगी।

स्वच्छता में लापरवाही नहीं, वार्ड-33 का निरीक्षण

इंदौर। आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने गुरुवार सुबह झोन क्रमांक 7 के अंतर्गत वार्ड 33 का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद मनोज मिश्रा,अपर आयुक्त प्रखर सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आयुक्त ने सुखलिया, बापट चौराहा,रजिस्ट्रार गार्डन सहित आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण, सड़क एवं नाली सफाई तथा उद्यानों के रखरखाव की समीक्षा की।

उन्होंने निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थलों और बाजार क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता बनाए रखी जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने रहवासियों से जलप्रदाय,सीवरेज और विकास कार्यों को लेकर फीडबैक भी लिया। नागरिकों के सुझावों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही इंदौर स्वच्छता में अपना अग्रणी स्थान बनाए रख सकता है।

9.7 किमी एलिवेटेड कॉरिडोर पर घमासान

650 करोड़ की परियोजना हाईकोर्ट पहुंची

फ्इंदौर। देश के स्वच्छता में अग्रणी शहर इंदौर अब एक बहुचर्चित आधारभूत संरचना परियोजना को लेकर विवादों में है। एलआईजी से भंवरकुआं तक प्रस्तावित 9.7 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शहर के वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इंजीनियर और शहरी योजनाकार अतुल सेठ ने जनहित याचिका दायर कर इस परियोजना पर रोक लगाने की मांग की है। मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।

परियोजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। उस समय तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की पहल पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। समय के साथ अनुमानित लागत बढ़कर करीब 650 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बावजूद यातायात समस्या का व्यापक समाधान संभव नहीं दिखता। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार इस एलिवेटेड कॉरिडोर से कुल ट्रैफिक का लगभग 18 प्रतिशत ही लाभान्वित होगा, जबकि शेष वाहन नीचे की सड़कों का ही उपयोग करेंगे।

वैकल्पिक मॉडल का सुझाव

अतुल सेठ का तर्क है कि लंबा कॉरिडोर बनाने के बजाय प्रमुख चौराहों पर सीमित दूरी के फ्लाईओवर बनाए जाएं। उनके अनुसार यदि लगभग 4 किलोमीटर का चरणबद्ध निर्माण किया जाए तो उपयोगिता 40 प्रतिशत से अधिक हो सकती है और लागत भी अपेक्षाकृत कम रहेगी। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्माण लागत के अतिरिक्त बिजली, पानी और सीवरेज लाइनों के स्थानांतरण पर लगभग 225 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

समय सीमा और जन असुविधा

परियोजना के पूर्ण होने में करीब पांच वर्ष का समय लगने का अनुमान है। इस अवधि में शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पर यातायात प्रभावित रहने की आशंका जताई गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि छोटे और चरणबद्ध फ्लाईओवर ढाई से तीन वर्ष में तैयार किए जा सकते हैं, जिससे आमजन को कम असुविधा होगी।

सर्वे रिपोर्ट पर भी सवाल

इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) द्वारा पूर्व में कराए गए सर्वेक्षणों में उपयोगिता का प्रतिशत काफी कम बताया गया था। शुरुआती आकलन में इसे 3 से 8 प्रतिशत के बीच बताया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने उस समय परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया था। बाद में संशोधित सर्वे के लिए अतिरिक्त व्यय किया गया। अब पुनः उसी मार्ग पर एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने से सवाल खड़े हो रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि बड़े पिलर और संरचनात्मक ढांचे के कारण सड़क की उपयोगी चौड़ाई कम हो सकती है, जिससे जाम की स्थिति और जटिल हो सकती है। वहीं, चरणबद्ध फ्लाईओवर मॉडल को अपेक्षाकृत पर्यावरण-अनुकूल और यातायात प्रबंधन के लिहाज से व्यावहारिक बताया गया है। अब शहर में इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या अदालत इस परियोजना को यथावत जारी रखने की अनुमति देगी या फिर वैकल्पिक प्रस्तावों पर पुनर्विचार का निर्देश देगी। आने वाले समय में अदालत का रुख ही तय करेगा कि यह बहुप्रतीक्षित निर्माण योजना किस दिशा में आगे बढ़ती है।

150 फीट ऊपर 'हवाई रेस्टोरेंट' पर हाईकोर्ट सख्त, याचिका पर नोटिस

अदालत ने सुरक्षा और अनुमति को लेकर गंभीर सवाल उठाए

इंदौर। शहर के बायपास क्षेत्र में क्रेन के सहारे लगभग 150 फीट की ऊंचाई पर संचालित कथित 'ऊबुद हवाई रेस्टोरेंट' अब कानूनी विवादों में घिर गया है। इस अनोखी लेकिन संभावित रूप से जोखिमपूर्ण गतिविधि को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं और जवाब तलब किया है।

यह जनहित याचिका अधिवक्ता चर्चित शास्त्री द्वारा दायर की गई है। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित रेस्टोरेंट को किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति प्रदान नहीं की गई है। निगम ने यह भी जानकारी दी कि 13 नवंबर 2025 को संचालकों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें संचालन रोकने या आवश्यक स्वीकृतियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद गतिविधियां जारी रहने का आरोप लगाया गया है।

'मौत का झूला' करार

याचिका में कहा गया है कि इस रेस्टोरेंट में एक बार में 30 से अधिक लोगों को क्रेन के माध्यम से लगभग 150 फीट ऊपर ले जाकर भोजन परोसा जाता है। इसमें शराब और मांसाहार भी परोसे जाने का उल्लेख है। याचिकाकर्ता ने इसे 'मौत का झूला' बताते हुए अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि यदि तकनीकी खराबी, यांत्रिक विफलता या मौसम संबंधी प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है तो गंभीर हादसा हो सकता है।

किन विभागों से अनुमति – याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या अग्नि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, संरचनात्मक स्थिरता, बीमा कवरेज और आपातकालीन निकासी (इवैक्यूएशन) जैसी अनिवार्य व्यवस्थाओं का परीक्षण किया गया है या नहीं। इतनी ऊंचाई पर संचालित व्यावसायिक गतिविधि के लिए किन-किन विभागों से अनुमति आवश्यक है, यह भी जांच का विषय बना हुआ है।

प्रशासनिक निगरानी पर प्रश्न– बायपास जैसे व्यस्त क्षेत्र में खुलेआम इस तरह का संचालन होने से प्रशासनिक निगरानी और सुरक्षा मानकों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। याचिका में यह तर्क दिया गया कि यदि बिना अनुमति इस प्रकार का आयोजन संचालित हो रहा है तो यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है।

10 मार्च को अगली सुनवाई– खंडपीठ ने दोनों पक्षों को विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को निर्धारित की गई है। तब तक यह स्पष्ट होगा कि संबंधित संचालकों ने आवश्यक अनुमतियां ली हैं या नहीं, और प्रशासन इस पूरे प्रकरण में क्या रुख अपनाता है। फिलहाल, यह मामला केवल एक अनोखे रेस्टोरेंट की अवधारणा का नहीं, बल्कि शहरी क्षेत्रों में रोमांच के नाम पर सुरक्षा मानकों से समझौते के आरोपों का बन गया है। हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर अब सभी की नजरें टिकी हैं।

चंदन नगर में कारों के कांच तोड़ने वाले का पुलिस ने जुलूस निकाला

लोगों ने पुलिस कार्रवाई को सही माना, सम्मान किया गया

इंदौर। चंदन नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कारों के कांच तोड़ने वाले आरोपी का घटनास्थल पर जुलूस निकाला। पुलिस चौकी और एक पूर्व पार्षद की कार में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी के खिलाफ की गई इस कार्रवाई को क्षेत्र में कानून का भय स्थापित करने की कवायद माना जा रहा है। मामला चंदन नगर क्षेत्र का है, जहां सावन पिता आज़ाद नरवले, निवासी राजमोहल्ला, ने पुलिस चौकी और पूर्व पार्षद के वाहन में तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे उसी इलाके में ले जाया गया, जहां उसने तोड़फोड़ की थी। जुलूस के दौरान थाना प्रभारी तिलक करोले के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस की मौजूदगी में आरोपी को पैदल पूरे क्षेत्र में घुमाया गया, ताकि आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हो सके।

लोगों की भीड़, और समर्थन– आरोपी के जुलूस की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी घरों और सड़कों पर निकल आए। लोगों ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन करते हुए तालियां बजाई और आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग दोहराई। क्षेत्रवासियों का कहना था कि इस तरह की कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में भय पैदा होगा। जुलूस के दौरान क्षेत्रीय रहवासियों ने थाना प्रभारी तिलक करोले को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। नागरिकों ने कहा कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है और पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।

पूर्वी रिंग रोड व इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन के विरोध में किसान-हंगामा

कलेक्ट्रेट पर अर्धनग्न होकर किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया

इंदौर। कलेक्ट्रेट परिसर गुरुवार को उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब पूर्वी रिंग रोड परियोजना और इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन के विरोध में प्रभावित किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। तेज गर्मी के बीच एक बुजुर्ग किसान की तबीयत बिगड़ गई और वे जमीन पर लेट गए। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने पानी देने की कोशिश की,लेकिन किसानों ने यह कहते हुए मना कर दिया 'हम अपना पानी पिएंगे, सरकार का नहीं।' प्रदर्शनकारियों का दावा है कि प्रस्तावित अलाइनमेंट से करीब 44 गांवों की सिंचित और अति उपजाऊ कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। किसानों के अनुसार, इस जमीन पर साल में तीन से चार फसलें ली जाती हैं। उन्होंने बिना सहमति अधिग्रहण को

मौलिक अधिकारों का हनन बताया।

मुआवजे पर उठे सवाल– किसानों ने मांग की कि वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार कम से कम चार गुना मुआवजा दिया जाए। साथ ही परियोजना का रूट 5.6 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने की मांग भी दोहराई। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और उग्र होगा।

लोकायुक्त ने पांच हजार रू की रिश्वत लेते पर्यवेक्षक को पकड़ा

आंगनवाड़ी नियुक्ति में रिश्वत का खेल उजागर हुआ

इंदौर। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती के बीच लोकायुक्त इंदौर इकाई ने एक बड़ी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की संविदा पर्यवेक्षक को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है।

मामले के अनुसार, आवेदिका सलिता पालवी आंगनवाड़ी केंद्र-1 मोजवारी, तहसील खालवा जिला खंडवा में सहायिका के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र-3 में कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि सेक्टर सावली की पर्यवेक्षक अजिला मोहे ने पहले सहायिका पद पर नियुक्ति के लिए 5 हजार रुपये तथा कार्यकर्ता पद पर पदस्थापना के लिए 2 लाख रुपये की मांग की। कुल 2 लाख 5 हजार रुपये की डिमांड से आवेदिका परेशान हो गई।

शिकायत के बाद जाल बिछाया

पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज कराई। सत्यापन के दौरान आरोप सही पाए गए।

इसके बाद गुरुवार को ट्रैप दल का गठन किया गया। योजना के तहत जैसे ही आरोपी ने 5 हजार रुपये की पहली किस्त ली, टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। ट्रैप दल में निरीक्षक प्रतिभा तोमर, निरीक्षक आशुतोष मिठास सहित अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लोकायुक्त अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि मामले में आगे और खुलासे संभव हैं।

डीएवीवी के परीक्षार्थी नहीं होने पर भी तैयार होंगे 22 विषयों के परचे

11 विषय खाली, फिर भी पेपर और टाइम टेबल जारी करना होगा

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) की आगामी स्नातक चतुर्थ वर्ष की परीक्षाओं में एक विचित्र स्थिति सामने आई है। नई शिक्षा नीति (एनईपी) के अंतर्गत मार्च माह से आयोजित होने वाली परीक्षाओं में बीए और बीएससी के 22 विषय ऐसे हैं, जिनमें पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या शून्य है। इसके बावजूद, विश्वविद्यालय प्रशासन नियमानुसार इन सभी विषयों के प्रश्न पत्र तैयार करने और टाइम टेबल जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है।

नियम का पालन प्राथमिकता

विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, किसी भी पाठ्यक्रम की परीक्षा प्रक्रिया को रोकना संभव नहीं है। भले ही वर्तमान में कोई छात्र न हो, लेकिन सिस्टम को अपडेट रखने और अंतिम समय में किसी छात्र के आवेदन की संभावना को देखते हुए सभी 40 विषयों के पेपर सेट करना अनिवार्य है।

बीए: कुल 22 विषयों में से केवल 12 में छात्र मौजूद हैं, जबकि 10 विषय रिक्त हैं।

बीएससी: 18 विषयों में से केवल 7 में प्रवेश हुए हैं, शेष 11 में कोई नामांकन नहीं है।

संख्या में भारी गिरावट

इस सत्र में चौथे वर्ष के विद्यार्थियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष जहां 3,500 छात्र थे, वहीं इस बार यह संख्या आधे से भी कम रह गई है। सर्वाधिक रुझान बीए में राजनीति विज्ञान (222 छात्र) और बीएससी में वनस्पति विज्ञान (216 छात्र) सबसे लोकप्रिय विषय रहे। परीक्षाएं 5 मार्च से प्रस्तावित हैं। परीक्षार्थियों की अल्प संख्या को देखते हुए इंदौर शहर में केवल दो कॉलेजों (जीएससीसी और न्यू जीडीसी) को केंद्र बनाया गया है। जिले के बाहर भी सरकारी कॉलेजों को केंद्र की सूची में रखा गया है, हालांकि वहां उपस्थिति नगण्य रहने की उम्मीद है।

रिसर्च के प्रति उदासीनता

नई शिक्षा नीति के तहत 'ऑनर्स विद रिसर्च' जैसे उन्नत पाठ्यक्रमों को लेकर छात्रों का उत्साह काफी कम दिखा।

बीए: मात्र 1 छात्र ने रिसर्च का विकल्प चुना।

बीएससी: केवल 2 छात्रों ने इस क्षेत्र में रुचि दिखाई।

बीकॉम: यहां स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक है, जहां 27 छात्र रिसर्च कोर्स का हिस्सा बने हैं।

परीक्षा नियंत्रक का बयान – प्रो अशेष तिवारी के अनुसार, कई विषयों में छात्र संख्या शून्य होने के बावजूद प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी आकस्मिक आवेदन पर परीक्षा आयोजित की जा सके और विश्वविद्यालय का परीक्षा तंत्र पूरी तरह तैयार रहे।

संपादकीय

आप की नैतिक जीत

दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा मुख्य आरोपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी 7 आरोपियों को बरी किया जाना आम आदमी पार्टी की नैतिक जीत है। आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया है। हालांकि इस मामले की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई ने फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाने की बात कही है, लेकिन यह संदेह शुरू से ही था कि यह पूरा मामला भाजपा को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए है और पिछले साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका फायदा मिला। उसने 11 साल से दिल्ली में जमी आप सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। दिल्ली कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि शराब नीति घोटाले की हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं और उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। सीबीआई सिसोदिया के खिलाफ पहली नजर में भी मामला साबित नहीं कर पाई। केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया।

चार्जशीट में ऐसी कई बातें शामिल की गईं, जिनका गवाहों के बयानों से कोई संबंध नहीं है। चार्जशीट में विरोधाभास हैं, जो कथित साजिश की पूरी थ्योरी को कमजोर करते हैं। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए जज ने कहा कि हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं थी। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया पर आरोप था कि वे शराब नीति बनाने और लागू करने के जिम्मेदार थे, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और न ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई। उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिल्ली शराब नीति को लेकर CAG (कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) की रिपोर्ट लीक हुई थी। इसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि शराब नीति में काफी गड़बड़ियां थीं, जिनमें लाइसेंस देने में खामी भी शामिल है। इसके साथ ही आप नेताओं को कथित तौर पर घूस के जरिए फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुआई कर रहे थे, उसने एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया था। कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दे दी थी और कई अहम फैसलों पर तब के उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली गई थी। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI दोनों जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किया था। ED ने उन्हें 21 मार्च 2024 को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। इसके बाद 26 जून को CBI ने जेल से ही उन्हें हिरासत में ले लिया था। ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल ने भावुक होकर कि आज सत्य की जीत हुई है। ये केस झूठा था। जाहिर है कि दिल्ली कोर्ट के फैसले से इस धारणा की पुष्टि हो गई है कि पूरा मामला भ्रष्टाचार और अनियमितता का कम और राजनीतिक साजिश का ज्यादा था। इस फैसले से जहां सीबीआई कार्यक्षमता पर एक बार फिर प्रश्नचिन्ह लगा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा है। आम आदमी पार्टी को इस फैसले का लाभ अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। उनकी नैतिक जमीन मजबूत हुई है। अब आप ने भी सीबीआई के खिलाफ ऊंची अदालत में जाने का ऐलान कर दिया है।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार - लोकतंत्र की बड़ी चुनौती

भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था महाभियोग के माध्यम से की गई है। यह प्रक्रिया 'सिद्ध दुराचार या अक्षमता' के आधार पर संसद द्वारा पूरी की जाती है। किंतु इस प्रक्रिया की शर्तें अत्यंत कठोर हैं। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। इतिहास में देखा गया है कि महाभियोग की कार्यवाही बहुत कम मामलों में अंत तक पहुंची है। कई बार न्यायाधीशों ने प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया, और कई बार राजनीतिक मतभेदों के कारण आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। यद्यपि इन कठोर प्रावधानों का उद्देश्य न्यायपालिका को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना है, फिर भी इससे यह धारणा बनती है कि जवाबदेही की प्रक्रिया प्रभावी नहीं है।

नजरिया
नृपेन्द्र अभिषेक नृप
लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

किसी भी लोकतांत्रिक समाज में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील और दूरगामी परिणामों वाला विषय होता है। हाल के समय में भारत में यह बहस तेज हुई कि क्या आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं, जैसे भ्रष्टाचार, मुकदमों की लंबित संख्या और न्यायाधीशों की कमी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। यह विवाद तब सामने आया जब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका' शीर्षक से एक संशोधित अध्याय शामिल किया गया। इस अध्याय की प्रस्तुति को लेकर देश के प्रधान न्यायाधीश ने आपत्ति जताई और संकेत दिया कि यह विषय जिस तरह से रखा गया है, वह एक सोची-समझी कोशिश भी हो सकती है। यद्यपि यह बहस जारी है कि बच्चों को किस उम्र में किस प्रकार की नागरिक शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन एक बात स्पष्ट है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों और घटनाओं को केवल पाठ्यपुस्तक से हटाकर सार्वजनिक चर्चा से समाप्त नहीं किया जा सकता।

न्यायपालिका किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में अत्यंत सम्मानित और विशिष्ट स्थान रखती है। वह संविधान की संरक्षक होती है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और राज्य तथा नागरिकों के बीच उत्पन्न विवादों का अंतिम निर्णय देती है। इसलिए न्यायपालिका की निष्पक्षता और ईमानदारी पर जनता का विश्वास लोकतंत्र की स्थिरता की आधारशिला है। कार्यपालिका और विधायिका जहाँ राजनीतिक वातावरण में कार्य करती हैं और चुनावी जवाबदेही के अधीन रहती हैं, वहीं न्यायपालिका की वैधता उसकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और नैतिक गरिमा पर टिकी होती है। यही कारण है कि यदि न्यायपालिका के किसी सदस्य पर भी अनैतिक आचरण का आरोप लगता है, तो उसका प्रभाव व्यापक और गहरा होता है।

हाल के वर्षों में कुछ मामलों ने न्यायिक जवाबदेही को लेकर असहज प्रश्न खड़े किए हैं। विशेष रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़ा विवाद काफी चर्चा में रहा। समाचारों में यह आरोप सामने आया कि उनके निवास से करोड़ों रुपये के आंशिक रूप से जले हुए नोट बरामद हुए। यद्यपि उनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ किए जाने की बात कही गई, परंतु अभी तक वह अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी है और वे पद पर बने हुए हैं। यह मामला ही नहीं, बल्कि अतीत में अन्य न्यायाधीशों से जुड़े आरोप भी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि गंभीर आरोपों की जांच और दंड की प्रक्रिया कितनी जटिल और लंबी है।

भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था महाभियोग के माध्यम से की गई है। यह प्रक्रिया 'सिद्ध दुराचार या अक्षमता' के आधार पर संसद द्वारा पूरी की जाती है। किंतु इस प्रक्रिया की शर्तें अत्यंत कठोर हैं। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। इतिहास में देखा गया है कि महाभियोग की कार्यवाही बहुत कम मामलों में अंत तक पहुंची है। कई बार न्यायाधीशों ने प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया, और कई बार राजनीतिक मतभेदों के कारण आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। यद्यपि इन कठोर प्रावधानों का उद्देश्य न्यायपालिका को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना है, फिर भी इससे यह धारणा बनती है कि जवाबदेही की प्रक्रिया प्रभावी नहीं है।

यह कहना गलत होगा कि भ्रष्टाचार केवल न्यायपालिका तक सीमित है। भ्रष्टाचार एक व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक समस्या है, जो शासन के सभी अंगों विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक संस्थाओं को प्रभावित करती है। फिर भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का प्रभाव विशेष रूप से घातक होता है। यदि लोगों को यह विश्वास हो जाए कि न्याय खरीदा या प्रभावित किया जा सकता है, तो कानून का शासन कमजोर पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में लोग न्याय पाने के लिए वैधानिक रास्तों के बजाय अन्य उपायों का सहारा लेने लगते हैं, जिससे सामाजिक अस्थिरता और अराजकता बढ़ सकती है।

भारतीय न्यायिक व्यवस्था के सामने एक और बड़ी चुनौती लंबित मामलों का भारी बोझ है। विभिन्न अदालतों में करोड़ों मामले वर्षों से लंबित हैं। न्यायाधीशों की कमी, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, जटिल प्रक्रियाएं और बार-बार स्थगन, ये सभी कारण मिलकर समस्या को और गंभीर बनाते हैं। यद्यपि लंबित मामलों की अधिकता को सीधे भ्रष्टाचार नहीं कहा जा सकता, लेकिन अत्यधिक विलंब से अनैतिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलने की संभावना रहती है। जब न्याय पाने में वर्षों लग जाते हैं, तो कुछ लोग शॉर्टकट अपनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार व्यवस्था की कमजोरी और भ्रष्टाचार एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं।

शैक्षिक पाठ्यक्रम से जुड़ा विवाद एक गहरे दार्शनिक प्रश्न को जन्म देता है, क्या बच्चों को संस्थागत कमजोरियों से परिचित कराया जाना चाहिए, या उन्हें केवल आदर्श सिद्धांतों तक सीमित रखा जाना चाहिए? एक पक्ष यह मानता है कि कम उम्र में ऐसी जानकारी देने से संस्थाओं के प्रति सम्मान घट सकता है। दूसरा पक्ष कहता है कि लोकतंत्र में सजग और जागरूक नागरिक तैयार करना आवश्यक है। यदि बच्चों को संतुलित और तथ्यपूर्ण जानकारी दी जाए, जिसमें समस्याओं के साथ-साथ सुधार की प्रक्रियाओं और ईमानदार उदाहरणों का भी उल्लेख हो—तो यह शिक्षा नकारात्मकता नहीं, बल्कि जागरूकता पैदा करेगी।

यह भी सच है कि भारतीय न्यायपालिका ने अनेक ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से साहस और स्वतंत्रता का परिचय दिया है। अदालतों ने मौलिक अधिकारों का विस्तार किया, पर्यावरण संरक्षण को मजबूती दी, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित किया और कई संवेदनशील मामलों में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की। अनेक न्यायाधीशों ने निष्कलंक सेवा और उच्च नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसलिए भ्रष्टाचार पर चर्चा करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कुछ आरोपों के आधार पर पूरी संस्था को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।

समय-समय पर न्यायिक सुधारों के प्रस्ताव भी सामने आते रहे हैं। इनमें एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र की स्थापना, संपत्ति की पारदर्शी घोषणा, आंतरिक आचार संहिता को सुदृढ़ करना, अदालतों का डिजिटलीकरण और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना शामिल हैं। ई-कोर्ट, वर्चुअल सुनवाई और ऑनलाइन केस ट्रैकिंग जैसी तकनीकी पहलें पारदर्शिता बढ़ा सकती हैं और अनियमितताओं की संभावनाओं को कम कर सकती हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर भी बहस जारी है। किंतु हर सुधार में यह संतुलन बनाए रखना होगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित न हो, साथ ही जवाबदेही भी सुनिश्चित हो।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर चर्चा संयमित, तथ्यों पर आधारित और सुधार की भावना से प्रेरित होनी चाहिए। अतिरंजित आरोप या राजनीतिक हमला संस्था को कमजोर कर सकते हैं, जबकि मौन या इनकार से समस्या गहरी हो सकती है। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने का साहस दिखाए। पाठ्यपुस्तक से जुड़े विवाद के मूल में यही द्वंद्व है, संस्था की प्रतिष्ठा बनाम पारदर्शिता। यदि शैक्षिक सामग्री से समस्याओं का उल्लेख हटा भी दिया जाए, तो वास्तविकता नहीं बदलती। बल्कि जागरूक नागरिक ही भविष्य में सुधार की राह प्रशस्त कर सकते हैं। नागरिक शिक्षा का उद्देश्य प्रचार नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण समझ विकसित करना होना चाहिए।

वास्तव में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का प्रश्न इसलिए गंभीर है क्योंकि यह न्याय की नैतिक नींव को हिला सकता है। जवाबदेही की प्रक्रियाओं को मजबूत करना, लंबित मामलों को कम करना और न्यायाधीशों की कमी दूर करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे बढ़कर, जनता का विश्वास बनाए रखना ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र अपनी कमियों को स्वीकार करने से कमजोर नहीं होता; वह तब कमजोर होता है जब वह उन्हें छिपाने का प्रयास करता है। आगे का मार्ग छिपाने में नहीं, बल्कि सुधार और पारदर्शिता में निहित है।

बढ़ती आक्रामकता : युवाओं के मन का मौन संकट

मुद्दा
ममता कुशवाहा
लेखक शिक्षक हैं।

हाल के वर्षों में बच्चों और युवाओं के बीच बढ़ती हिंसक प्रवृत्तियाँ समाज के लिए गहरी चिंता का विषय बन गई हैं। आए दिन आक्रामक व्यवहार, मारपीट, बुलिंग और यहाँ तक कि गंभीर अपराधों में किशोरों की संलिप्तता की खबरें सामने आती हैं, जो पूरे समाज को झकझोर देती हैं। बच्चे और युवा किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। यदि उनकी ऊर्जा और क्षमता रचनात्मक दिशा में जाने के बजाय विनाशकारी रास्तों पर मुड़ने लगे, तो यह केवल व्यक्तिगत असफलता नहीं, बल्कि परिवार, समाज और व्यवस्था की गहरी समस्या का संकेत है। आज जिस तरह आक्रामकता को सामान्य व्यवहार की तरह स्वीकार किया जाने लगा है, वह इस बात का प्रमाण है कि यह कोई एक-दो घटनाओं तक सीमित समस्या नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक चुनौती है, जिस पर गंभीरता से विचार और कार्य करने की आवश्यकता है।

इस बढ़ती हिंसा के पीछे जिन कारणों पर सबसे अधिक चर्चा होती है, उनमें डिजिटल मीडिया का प्रभाव प्रमुख है। आज के बच्चे और किशोर ऑनलाइन गेम, वेब सीरीज़ और सोशल मीडिया की दुनिया में डूबे रहते हैं, जहाँ हिंसक दृश्य और आक्रामक व्यवहार को अक्सर मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब कोमल और संवेदनशील मन बार-बार आक्रामकता और हिंसा से भरे दृश्य देखते हैं, तो धीरे-धीरे उनके मन में वास्तविक और आभासी दुनिया के बीच का अंतर धुंधला पड़ने लगता है। लगातार ऐसे दृश्य देखने से संवेदनशीलता कम हो सकती है और हिंसा को लेकर मन की प्रतिक्रिया सुस्त पड़ जाती है। हालांकि हर हिंसक घटना के लिए केवल डिजिटल माध्यमों को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि इनका प्रभाव बच्चों के विचार, भाषा और व्यवहार पर पड़ता है। यदि सही मार्गदर्शन औरसंतुलित निगरानी न हो, तो यह प्रभाव उनके व्यक्तित्व को नकारात्मक दिशामें मोड़ सकता है।

परिवार का वातावरण भी बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घर ही वह पहला स्थान है जहाँ बच्चा जीवन के मूल्यों, भावनात्मक व्यवहार और समस्याओं से निपटने के तरीकों को सीखता है। यदि घर का वातावरण तनावपूर्ण हो, माता-पिता के बीच निरंतर झगड़े होते हों, कठोर अनुशासन या उपेक्षा का माहौल हो, या नशे जैसी बुरी आदतें मौजूद हों, तो बच्चे के मन में असुरक्षा और आक्रोश पनप सकता है। जब उसकी भावनात्मक आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं और उसे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता, तो भीतर जमा हुआ तनाव कभी-कभी आक्रामकता के रूप में बाहर आता है। अत्यधिक अपेक्षाएँ भी बच्चों पर मानसिक दबाव डालती हैं, विशेषकर पढ़ाई और करियर को लेकर। जब बच्चा स्वयं को समझा या स्वीकार किया हुआ महसूस नहीं करता, तो उसके भीतर असंतोष और विद्रोह की भावना जन्म ले सकती है। इसके विपरीत, यदि परिवार में संवाद, स्नेह और संतुलित अनुशासन का वातावरण हो, तो बच्चे के मन में स्थिरता और सुरक्षा की भावना विकसित होती है, जो उसे हिंसक प्रवृत्तियों से दूर रखती है।

साथियों का प्रभाव और आपसी तुलना भी इस समस्या को बढ़ाते हैं। किशोरावस्था वह समय है जब व्यक्ति अपनी पहचान खोजता है और मित्रों से स्वीकृति पाना चाहता है। यदि किसी समूह में दबंगई, डराना-धमकाना या जोखिमभरा व्यवहार लोकप्रियता का साधन बन जाए, तो कई किशोर उसी राह पर चलने लगते हैं। सोशल मीडिया इस प्रवृत्ति को और तेज कर देता है, क्योंकि वहाँ सफलता, सुंदरता और संपन्नता की चमकदार तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं। इनसे तुलना करके कई युवा स्वयं को कमतर समझने लगते हैं। यह हीनभावना कभी-कभी गुस्से और आक्रोश में बदल जाती है। कुछ युवा अपनी कमजोरी को छिपाने या नियंत्रण जताने के लिए आक्रामक व्यवहार का सहारा लेते हैं, जो धीरे-धीरे आदत बन सकता है।

विद्यालय का वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्कूल केवल पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास का केंद्र होता है। लेकिन जब कक्षाएँ भीड़भाड़ से भरी हों, प्रतिस्पर्धा अत्यधिक हो और परामर्श सेवाएँ सीमित हों, तो छात्रों की मानसिक समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा पाता। बुलिंग, चाहे वह शारीरिक हो या ऑनलाइन, आज एक गंभीर समस्या है। बुलिंग का शिकार होने वाले बच्चे चिंता, अवसाद और क्रोध से गुजरते हैं, जबकि ऐसा करने वाले बच्चे भी अक्सर किसी आंतरिक पीड़ा या असुरक्षा से जूझ रहे होते हैं। यदि समय रहते हस्तक्षेप न किया जाए, तो यह चक्र और अधिक खतरनाक रूप ले सकता है। इसलिए स्कूलों में सुदृढ़ परामर्श व्यवस्था, स्पष्ट नियम और संवेदनशील वातावरण की आवश्यकता है, जहाँ हर बच्चा सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।

सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ भी युवाओं के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता और अपराध से घिरे वातावरण में पलने वाले बच्चों पर निरंतर तनाव बना रहता है। जब उन्हें आगे बढ़ने के अवसर सीमित दिखाई देते हैं, तो उनके मन में निराशा और हताशा जन्म ले सकती है। समाज में शक्ति और बदले की भावना को महिमा मंडित करने वाली सोच भी हिंसा को एक वैध साधन के रूप में प्रस्तुत करती है। ऐसे में केवल व्यक्तिगत स्तर पर सुधार पर्याप्त नहीं होता; व्यापक सामाजिक बदलाव भी आवश्यक होते हैं, जो समान अवसर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करें।

बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। चिंता, अवसाद, ध्यान की समस्या या किसी आघात का असर यदि समय पर समझा और संभाला न जाए, तो वह चिड़चिड़ापन और आक्रामकता में बदल सकता है। दुर्भाग्य से कई स्थानों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ या तो उपलब्ध नहीं हैं या उनके प्रति सामाजिक झिझक बनी रहती है। कई बार माता-पिता या शिक्षक बच्चे की परेशानी को अनुशासनहीनता समझ लेते हैं और दंड का सहारा लेते हैं, जबकि उसे समझ और सहारे की आवश्यकता होती है। यदि समय रहते पहचान औरपरामर्श मिल जाए, तो स्थिति को सुधारा जा सकता है। फिर भी यह याद रखना आवश्यक है कि युवावस्था ऊर्जा, रचनात्मकता और उत्साह का समय है। सही दिशा और मार्गदर्शन मिलने पर यही ऊर्जा समाज के निर्माण में लग सकती है। खेल, कला, संगीत, पठन-पाठन और सामाजिक सेवा जैसी गतिविधियाँ बच्चों को सकारात्मक मंच देती हैं, जहाँ वे अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। परिवार में खुला संवाद, जहाँ बच्चा बिना डर अपनी बात कह सके, हिंसक प्रवृत्तियों को रोकने का प्रभावी उपाय है।

डिजिटल साक्षरता भी अत्यंत आवश्यक है। पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि वे मीडिया सामग्री को समझदारी से देखें और सही-गलत का विवेक विकसित करें। स्क्रीन समय पर संतुलित नियंत्रण और माता-पिता की सहभागिता विश्वास और समझ को मजबूत करती है। स्कूलों में भावनात्मक संतुलन, संवाद कौशल और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे आधुनिक चुनौतियों का सामना संयम से कर सकें।

बच्चों और युवाओं में बढ़ती हिंसक प्रवृत्तियाँ कई कारणों के मेल से उत्पन्न होती हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और तकनीकी सभी कारक इसमें भूमिका निभाते हैं। केवल दंड या आरोप-प्रत्यारोप से समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसके लिए सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता है। परिवार संवाद और स्नेह को प्राथमिकता दें, स्कूल भावनात्मक विकास को महत्व दें, समाज सुरक्षित और समान अवसर प्रदान करे, और नीतियाँ मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दें। यदि हम मिलकर बच्चों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें, तो यह चुनौती एक अवसर में बदल सकती है। बच्चों का संवेदनशील और संतुलित विकास केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है, ताकि आने वाली पीढ़ी एक अधिक शांत, सुरक्षित और सहृदय दुनिया का निर्माण कर सके।

जीवन भी एक रेलयात्रा है

अनुभव
- बृजेश प्रसाद

लंबे समय बाद अपने गाँव की ओर यात्रा करने का अवसर मिला। अवसर था—शादी-ब्याह और होली का मौसम। स्वाभाविक था कि रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई थी। ट्रेन कोलकाता से खुली और कुछ ही समय बाद अगले स्टेशन पर पहुँचते-पहुँचते भीड़ का सैलाब डिब्बों में उमड़ पड़ा।

लोग उत्साह, जल्दबाज़ी और थोड़ी-सी अधीरता के साथ डिब्बों में चढ़ रहे थे। किसी को खिड़की की सीट चाहिए थी, किसी को ऊपर की बर्थ। सीटों को लेकर झिझक, आग्रह और कहीं-कहीं हल्की नोकझोंक—मानो पूरी ट्रेन पर उसी का अधिकार हो। जिन यात्रियों के पास आरएसी टिकट थी, उनका हाल और भी दयनीय था। वे आधी सीट पर सिमटे हुए, अपने हिस्से के स्थान को बचाए रखने की चेष्टा कर रहे थे।

कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा—सामान रखने की जगह को लेकर तर्क-वितर्क, सीट के अधिकार को लेकर बहस। प्रत्येक व्यक्ति अपने छोटे-से दायरे को सुरक्षित रखने में लगा था। उस क्षण ऐसा प्रतीत होता था मानो यह स्थान स्थायी हो, मानो यही जीवन का अंतिम पड़ाव हो।

परंतु समय की रफ्तार किसी के लिए नहीं रुकती। धीरे-धीरे ट्रेन अपने आधे सफर को पार कर चुकी थी। अब वही यात्री, जो थोड़ी देर पहले अधिकार के लिए व्याकुल थे, शांत होकर बैठ गए थे। किसी ने बिस्तर समेटा, किसी ने थैला व्यवस्थित किया, कोई अपने गंतव्य के आने की प्रतीक्षा में खिड़की से बाहर देखने लगा।

एक-एक कर यात्री उतरते गए। डिब्बा धीरे-धीरे खाली होने लगा। जिन सीटों के लिए कुछ घंटे पहले विवाद हुआ था, वे अब निःशब्द और रिक्त पड़ी थीं—मानो कभी किसी ने उन पर अपना अधिकार जताया ही न हो।

इस दृश्य ने मन में एक गहरी अनुभूति जगाई—क्या जीवन भी ऐसी ही एक रेलयात्रा नहीं है?

यौवन के प्रारंभिक दिनों में हम 'मेरा' और 'तेरा' के भेद में उलझे रहते हैं। घर, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति—इन सब पर अपना अधिकार स्थापित करने की होड़ लगी रहती है। हम भूल जाते हैं कि हम यात्री हैं, स्वामी नहीं। यह यात्रा अस्थायी है और हर स्टेशन पर कोई-न-कोई उतरने वाला है। समय की रेलगाड़ी निरंतर आगे बढ़ती रहती है। धीरे-धीरे हम भी अपने अनुभवों को समेटते हैं, अपने मोह को सहेजते हैं और एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर अपनी अंतिम मंज़िल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। पीछे रह जाती हैं वे खाली सीटें, जो कभी हमारे अधिकार और अहंकार का प्रतीक थीं।

जीवन का सत्य सरल है—यह एक यात्रा है, पड़ाव नहीं। जो आज हमारा है, वह कल किसी और का होगा। इसलिए अधिकार से अधिक आवश्यक है—सहयात्रियों के प्रति सहानुभूति, और यात्रा के प्रति विनम्रता।

समर्थन करना हो या विरोध, बात टाइमिंग की है

व्यंग्य
मुकेश राठौर
लेखक व्यंग्यकार हैं।

बीते दिनों राजधानी में आयोजित 'इंडिया एआई इंपैक्ट समिट' में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मैडम साहिबा ने जाने या अनजाने में चीनी रोबोट डॉग को अपना बता दिया गया। पूछने पर सफाई भी दे डाली। एक बार तो लगा क्या हुआ जब ड्रैगन हमारी जमीन को अपना बता सकता है तो हम उसके आर्टिफिशियल डॉग को भी अपना नहीं बता सकते क्या? खैर...इस घटना से दुनिया में देश की छवि खराब होने से भयंकर आहत युवा कांग्रेसियों द्वारा किया गया शर्टलेस विरोध प्रदर्शन इन दिनों खासा चर्चा में है। यत्र-तत्र सर्वत्र उनके इस कृत्य की घनघोर निंदा हो रही है। आज देश दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी-वैसी बात होने पर सर्वाधिक आहत नेता ही होते हैं। नेताओं के पीछे पहले से आहत पब्लिक आहत हो जाए ये अलग बात है। भाजपाई कह रहे इनकी इस टाइप की हरकत से दुनिया में देश की छवि खराब हुई। इन्हें प्रदर्शन करना ही था तो समिट साइट से कहीं दूर जाकर एकांत में या जंतर-मंतर,इंडिया गेट...पर जाकर कर लेते,जो प्रायः प्रदर्शन करने के लिए ही जानी जाती है। दूसरी ओर कांग्रेस हाईकमान का मानना है कि उनके बब्बर शेरों ने शर्ट उतारकर जो किया बिल्कुल सही किया,सही के सिवा कुछ न किया। दलों के दावे जो भी हो आम नागरिक समझ नहीं पा रहा कि देश की छवि दीगर डॉग के प्रदर्शन से खराब हुई या देशभक्ति में शर्ट उतारने वालों से!

एक्चुअली विरोध ऐसा कृत्य है जो प्रदर्शन के लिए ही किया जाता है क्योंकि विरोध है भाई साहब कोई दान-धरम तो नहीं जो दाएं हाथ से करो और बायां बेखबर रहे। इधर तो दीवारों से कान और मोबाइल से आंख लगाए जितने ज्यादा लोग बाख़बर होंगे उतना अच्छा। समर्थन मौन रहकर भी किया जा सकता है लेकिन विरोध के लिए चीखना-चिल्लाना,तोड़-फोड़ करना, सार्वजनिक संपत्ति जलाना जरूरी सा हो जाता है। कभी लोग चक्का जाम कर,काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज करवाते थे। धीरे-धीरे बांह पर काली पट्टी बांध अपना विरोध जताने लगें,फिर कपड़े फाड़ने लगे अब अर्द्धनग्न होकर विरोध किया जाने लगा है। इसे प्रदर्शन करने वालों की समझदारी ही कहेंगे कि वे सिरीप आधे कपड़े उतार रहे हैं अव्वल तो यह कि बिचारे दूसरों के कपड़े उतारने के बरअक्स खुद के कपड़े उतार रहे हैं।

एक बात समझ लीजिए 'लोकतंत्र समर्थन से जन्मता है लेकिन विरोध से जिंदा रहता है।' इसमें सबको विरोध करने का अधिकार है बस टाइमिंग जरूरी है। समर्थन और विरोध की टाइमिंग के दो श्रेष्ठ उदाहरण महाभारत और रामायण में देखने को मिलते हैं। महाभारत में द्रोपदी के चीरहरण के समय भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे दिग्गजों का मौन धारण करना दुःशासन और दुर्योधन के पक्ष में अप्रत्यक्ष समर्थन था। गर वे मौके पर विरोध कर देते तो कदाचित महाभारत नहीं होता। उधर रामायण में भी श्रीराम के राज्याभिषेक के अवसर पर कैकई का हैप्पीलेस होकर कोप भवन में जाना विरोध की राइट च्वाइस टाइमिंग थी। काश! कैकेई श्रीराम के राज्याभिषेक का समर्थन कर देती तो श्रीराम न तो चौदह बरस का वनवास झेलते न रामायण बनती।

बहरहाल,कार्य कर्ता दुआ करता कि आया काम बस निर्विघ्न निपट जाए मगर विरोध करने वाला चाहता है यही वक्त है पूरी कर ले आरजू...!

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।
प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

वक्रोक्ति

चंद्रशेखर साकल्ले

लेखक मप्र जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

लिटफेस्ट, कवि गोष्ठी और रेल के आने का किस्सा

पहले तो कवियों को विश्वास नहीं हुआ कि कवि सम्मेलन नहीं हो रहे हैं। उन्हें लगा आयोजक षड्यंत्र पूर्वक उन्हें आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आयोजकों को फोन लगाया। आयोजकों ने कहा कि अब कविताएं धूल भरे मैदानों में अस्थायी मंच बनाकर आम आदमी को नहीं सुनाई जातीं। अब कविताएं ज़मीन पर बैठ कर भी नहीं सुनी जातीं। वहाँ पान और गुटखे नहीं होते। न ही बीड़ी सिगरेट का धुआँ होता है। कवियों को हूट भी नहीं किया जाता। अब कविताएं न्यूज चैनलों के साहित्यिक कार्यक्रमों और लिटफेस्ट में सजे-धजे हॉल में शांत वातावरण में सुनाई जाती हैं। यहाँ आमंत्रित श्रोता कुर्सियों पर बैठ कर कविता सुनते हैं। कविता सुनाने वाले भी बसों में धक्के खाते नहीं आते। हवाई जहाज से आते हैं। जब से आभिजात्य वर्ग में साहित्य फैशन बना है, कवि भी सेलिब्रिटी हो गए हैं।

कवि सम्मेलनों का स्वर्णिम दौर गुजर चुका था। हर कस्बे और शहर में साल में चार बार होने वाले कवि सम्मेलन अब अतीत बन चुके थे। कविगण उसके अवसान से अवसाद में थे। वे बड़ी शिद्दत से उन दिनों को याद कर रहे थे, जब वो कलफ लगे कुर्ते पर जाकिट पहन कर बड़ी शान से मंच पर चढ़ते थे। उनके गीतों की एक -एक पंक्ति पर तालियाँ बजती थीं। कुछ अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों की शोभा बढ़ाते थे। कुछ का दायरा आसपास के शहरों और कस्बों तक सीमित था और कुछ स्थानीय कवि सम्मेलनों में स्थानीय कवि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे।

पहले तो कवियों को विश्वास नहीं हुआ कि कि कवि सम्मेलन नहीं हो रहे हैं। उन्हें लगा आयोजक षड्यंत्र पूर्वक उन्हें आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आयोजकों को फोन लगाया। आयोजकों ने कहा कि अब कविताएं धूल भरे मैदानों में अस्थायी मंच बनाकर आम आदमी को नहीं सुनाई जातीं। अब कविताएं ज़मीन पर बैठ कर भी नहीं सुनी जातीं। वहाँ पान और गुटखे नहीं होते। न ही बीड़ी सिगरेट का धुआँ होता है। कवियों को हूट भी नहीं किया जाता। अब कविताएं न्यूज चैनलों के साहित्यिक कार्यक्रमों और लिटफेस्ट में सजे -धजे हॉल में शांत वातावरण में सुनाई जाती हैं। यहाँ आमंत्रित श्रोता कुर्सियों पर बैठ कर कविता सुनते हैं। कविता सुनाने वाले भी बसों में धक्के खाते नहीं आते। हवाई जहाज से आते हैं। जब से आभिजात्य वर्ग में साहित्य फैशन बना है, कवि भी सेलिब्रिटी हो गए हैं। अंत में आयोजकों ने हाथ जोड़कर कहा 'भैया, हम मध्यम श्रेणी के आयोजक हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम आपकी वहाँ एंट्री कर सकें।

आयोजकों से निराश कवियों ने कवि गोष्ठियों से काम चलाना चाहा पर, समस्या आयोजक और आयोजन-स्थल की थी। तभी एक ऐसा समाचार आयाकि कवि गोष्ठी करना अनिवार्य हो गया। हुआ यह कि केंद्र सरकार के रेल बजट में घोषणा की गई कि उनके कस्बे को रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा।यानि अब उनकेकस्बे में भी रेल आएगी। कस्बे की बड़ी पुरानी मांग स्वीकृत हुई। पूरा कस्बा खुशी से झूम उठा। इस शुभ अवसर पर कवियों ने भी तय किया कि कस्बे में रेल आने की खुशी में एक कवि गोष्ठी की जाए। गोष्ठी में सिर्फ़ रेल से संबंधित कविताएं पढ़ी जाएंगी।बस, फिर क्या था, गीत अंकुरित होने लगे। दोहों की फसल लहलहाने लगी। छंद पके फलों की तरह टप-टप कर गिरने लगे। सारे कवियों ने रेल पर कविताएं लिखा डालीं। यक्ष प्रश्न यह था कि कवि गोष्ठी कहाँ आयोजित की जाए।

सबकी निगाहें बलभदर जी पर गईं। बलभदर जी हेड कांस्टेबल से रिटायर हुए थे, पर कस्बे में एस पी साहब के नाम से सम्मानित थे। उनका कस्बे से सटा एक फार्महाउस था। वहाँ वे सब्जियाँ उगाते थे और गायें पालते थे। फार्महाउस में उनका बड़ा -सा बंगला था,जिसमें वे रहते थे। बलभदर जी संगीत प्रेमी थे, संगीत की महफिलें सजाते थे। बंगले में एक बड़ा हॉल था जिसमें म्यूजिक सिस्टम था, गद्दे बिछे थे और गाव तकिये लगे थे। अफवाह थी कि यहाँ गाने के साथ नाच भी होता था, पर किसी ने देखा नहीं था।

बलभदर जी ने कवियों का अनुरोध सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कवियों के सम्मान में समोसे और जलेबी भी बुलवा लिए,जो चाय औरबिस्कुट के अलावा थे। बलभदर जी ने कवियों के सामने एक छोटी-सी शर्त रखी कि वे भी अपने कुछ गीत सुनाएंगे,जिसे कवियों ने तुरंत मान लिया।

कवि गोष्ठी के दिन कवियों को अपने पुराने दिन याद आ गए। उन्होंने कुर्ते धुलवाए, उनमें कलफ लगवाया, जाकिट पहनी और कविताएं लेकर फार्म हाउस पहुँच गए। सबसे पहले बलभदर जी ने एक फिल्मी गीत सुनाया। 'शमा है शुहाना शुहाना।' फिर एक गैर फिल्मी गीत गाया। जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह राग पहाड़ी पर आधारित है। इसके बाद श्रीमती बलभदर ने हारमोनियम पर दो लोकगीत गाए। फिर कवियों का नंबर आया, जो अब तक बेचैन हो चुके थे। सबसे पहले श्रीमती 'कृष्णदासी'जी ने एक स्वागत गीत गया।

'मैं तो वारी जाऊँ रे
रेल तेरी सीटी पे'

इसकी धुन संतोषी माता की आरती से काफी मिलती-जुलती थी। बाल कविताओं के गीतकार 'भोलामन'जी ने एक बालगीत सुनाया।

' मीठी सीटी बजाती रेल आई
बच्चों को नानी घर लाई'

लोकगीतों के गायक 'सावन'जी ने स्वरचित गीत गाया।

'जैसे मिल गई हो
खोई हुई मुंदरी
ऐसे आई हो तुम
ओ रेल सुंदरी।'

मुक्त छंद के सशक्त हस्ताक्षर 'प्रहरी'जी ने कविता पढ़ी।

'जैसे स्वागत करता है किसान
आषाढ़ के बादल का
जैसे स्वागत करता है प्रेमी
प्रेमिका के कदमों की आहट का
जैसे स्वागत करता है सरकारी कर्मचारी
पहली तारीख का
आओ रेल मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ ।'

कविता को भरपूर दाद मिली।

प्रेम कविताओं के लिए प्रसिद्ध 'दीवाना'जी ने अपनी प्रेमिका पर पांच सौ से ज़्यादा कविताएं लिखी थीं। वे सिर्फ प्रेम कविताएं लिखते थे। उन्होंनेअपनी प्रेमिका का सम्पूर्ण नख-शिख वर्णन अपनी कविताओं में कर दिया था।वे अपनी प्रेमिका की जुल्फों के साये में सोते थे और उसकी पायल की छन-छन पर मयूर की तरह नाचते थे। उसके रूप पर हजार बार मर चुके थे, वैसे भौतिक रूप से जिंदा और स्वस्थ थे। उन्होंने पहली बार प्रेमिका से हट कर रेल पर कविता लिखी। हालांकि रूपक प्रेम का ही चुना।

'अश्रुजल से पथ सींचूं
पलकों से तेरी राह बुहारूं
तुम आ रही हो जिस ओर से
उस दिशा की आरती उतारूं ।

इस पर बहुत देर तक तालियाँ बजती रहीं।इसके बाद 'घायल'जी का नंबर आया।'घायल'जी के बाद 'पायल' जी को कविता पढ़नी थी। 'घायल' जी और 'पायल' जी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों एक-दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते थे।'घायल'जी 'पायल'जी को दो कौड़ी का कवि मानते थे, जबकि 'पायल' जी' घायल'जी को कवि ही नहीं मानते थे। 'घायल' जी स्थानीय कवि सम्मेलनों में मंच संचालक से सांठगांठ कर 'पायल'जी को वरिष्ठकवि घोषित कर अध्यक्ष बनवा देते थे और इस तरह कविता पढ़ने से वंचित करदेते थे।'पायल'जी भी कम नहीं थे। उन्होंने 'घायल'जीके प्रथम पुष्प यानीपहले कविता संग्रह के विमोचन के दिन अपने एक व्यवसायी मित्र से कह कर पासके कस्बे में कवि सम्मेलन रखवा दिया और कवियों के आने-जाने के लिए बस की व्यवस्था करवा दी।'घायल'जी ने विमोचन कार्यक्रम की भारी भरकम तैयारी की थी, पर उसमें गिनती के लोग ही पहुँचे थे। दोनों एक- दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। बहरहाल....'घायल'जी ने कविता पढ़ना शुरू किया।

' सिंगपिंग करती रेल आई
सिंगपिंग करती रेल आई ।'

'पायल'जी ने तुरंत हस्तक्षेप किया

'रेल तो छुक -छुक करती आती है,ये सिंगपिंग क्या है? '

'घायल'जी ने कहा 'ये काव्यात्मक प्रयोग है। '

'पायल'जी-प्रयोग तो है, पर एकदम बेतुका प्रयोग है।'

'घायल'जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा 'इसमें अलंकार देखिए। '

'पायल'जी ज़रा जोर से बोले 'मुझे तो कोई अलंकार नहीं दिख रहा है। बताइए

कौन -सा अलंकार है? '

'घायल'जी बात संभालते हुए बोले 'इसमें एक लय है। '

'पायल' जी और जोर से बोले 'लय को क्या चाटें,लय में तो कुत्ता भी भौंकता है

तो क्या उसे भी कवि मान लें। '

इतना सुनना था कि 'घायल'जी का पारा आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने 'पायल'जी का कुर्ता पकड़ा और खींचा।'पायल'जी ने उस कुर्ते कोपहनकर बड़े -बड़े कवि सम्मेलनों में भाग लिया था। कुर्ता चर्र से फटगया।''पायल'जी ने 'घायल'जी को धक्का दिया।'घायल'जी गिर गए। दोनों मेंहाथापाई होने लगी। देखते -देखते कवि गोष्ठी कुश्ती के अखाड़े में बदल गई। कुछ कवि 'घायल'जी के पक्ष में खड़े हो गए। कुछ 'पायल'जी के साथ हो गए।सारे कवि गुत्थमगुत्था होने लगे।तभी बलभदर जी की जोरदार आवाज गूंजी 'बंद करो ये सब, वरना गोली मार दूंगा। 'कवियों ने देखा सचमुच बलभदर जी अपनी दुनाली लिए खड़े थे।कवियों ने लड़ाई बंद की। बलभदर जी फिर गरजे 'भागो यहाँ से, आइंदा से कोई भी कवि मेरे पास आया तो गोली मार दूँगा। 'घबराए कवि बाहर भागे।

इसके बाद कस्बे में कवि गोष्ठी नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद सारे कवि फेसबुक में समा गए।अब वे रोज एक कविता पोस्ट करते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं और रात को लाइक्स गिनकर सो जाते हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

प्रमोद दीक्षित मलय

लेखक शिक्षक एवं शैक्षिक संवाद मंच के संस्थापक हैं।

जीवन में वैज्ञानिक विवेक एवं दृष्टिकोण आवश्यक

विज्ञान मानव को जीवन जीने की एक दृष्टि देता है। चिंतन की आधारभूमि भेंट कर चलने को उजास भरा पथ प्रदान करता है। वास्तव में विज्ञान जीवन से जडता, अविद्या, अंधविश्वास, अतार्किता एवं संशय से मुक्ति का नाम है। विज्ञान व्यक्ति को तर्कशील एवं प्रयोगधर्मी बनाकर सवाल खड़े करने की सामर्थ्य पैदा करता है। विज्ञान मानवीय मेधा का उच्चतम आदर्श है। वसुधा के सौंदर्य को अक्षुण्ण बनाये रखते हुए प्राणिमात्र के लिए प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपभोग का मार्गदर्शन ही विज्ञान है। विज्ञान में समस्या है तो समाधान भी, कल्पना है तो प्रयोग भी। सवाल हैं तो उत्तरों की तह तक पहुंच सत्य का साक्षात्कार करने का सत्संकल्प भी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के माध्यम से हम इस भाव एवं चेतना को सिंचित कर समृद्ध करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा युवाओं एवं बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विज्ञान अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से 1986 से प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी, 1928 को ही सी.वी. रमन ने लोक सम्मुख अपनी विश्व प्रसिद्ध खोज 'रमन प्रभाव' की घोषणा की थी। 'रमन प्रभाव' के लिए ही 1930 में सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। सी.वी. रमन एशिया के पहले भौतिक शास्त्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। अमेरिकन केमिकल सोसायटी ने 1998 में 'रमन प्रभाव' को अंतरराष्ट्रीय विज्ञान के इतिहास की एक युगान्तरकारी घटना के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वास्तव में 'रमन प्रभाव' के स्मरण के साथ ही मानव जीवन के सम्यक विकास के लिए वैज्ञानिक विवेक, चिंतन एवं दृष्टिकोण अपनाने का दिन है, जिसकी हमें जरूरत है।

चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म 7 नवम्बर, 1888 को तमिलनाडु में कावेरी के तट पर स्थित तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपकी माता पार्वती अम्मा कुशल गृहिणी एवं पिता चन्द्रशेखर भौतिक शास्त्र एवं गणित के प्राध्यापक थे। घर पर एक समृद्ध लघु पुस्तकालय था तो तार वाद्ययंत्रों का संचय भी। संगीत में रुचि के चलते वीणा वादन पिता जी की नित्य साधना थी। वीणा के तारों के कम्पन से निकली मधुर ध्वनि बालक रमन को अपनी ओर खींचती। वह सोचते कि इन तारों को छेड़ने से एक विशेष लय, प्रवाह, आरोह-अवरोह में मनमोहक ध्वनि कैसे उत्पन्न हो सकती है। यही जिज्ञासा बाद में उनके ध्वनि सम्बंधी शोधों का आधार भी बनी। चार वर्ष की उम्र में ही पिता का तबादला विशाखापट्टनम हो जाने से रमन की प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं शुरू हुई। यहां घर के सामने लहराता सागर का नीला जल रमन का ध्यान आकर्षित करता। बालमन सोचता कि घर और सागर के जल में यह अन्तर कैसे। मकान की खिड़की से वह सागर की लहरों को अठखेलियां करते देखते रहते मानो जल के नीलेपन के रहस्य का कोई तोड़ खोज रहे हों। रमन ने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में 1903 में बी.ए. में प्रवेश लिया और विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में प्रथम आकर गौरव अर्जित किया। 1907 में एम.ए. गणित प्रथम श्रेणी में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण किया। परास्नातक करते समय ही 1906 में 'प्रकाश विवर्तन' विषय पर शोध पत्र लिखा जो लंदन से प्रकाशित विश्व प्रसिद्ध पत्रिका 'फिलसोफिकल मैगजीन' में छपा। 1907 में ही आपने असिस्टेंट एकाउंटेंट जनरल के रूप में कलकत्ता में कार्यभार ग्रहण किया। पर रमन का मन तो विज्ञान की दुनिया में ही रमा था। फलतः एक दिन कार्यालय से घर आते समय वर्ष 1876 में स्थापित 'इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस' की प्रयोगशाला में सुबह-शाम चार-चार घंटे 'ध्वनि मेंकम्पन एवं कार्य' के क्षेत्र में प्रयोग करने लगे। वह स्कूली बच्चों को प्रयोगशाला लाकर विज्ञान के विभिन्न प्रयोग करके दिखाते ताकि बच्चेविज्ञान की दुनिया को करीब से देख-परख सकें।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति आशुतोष मुखर्जी के कहने पर 1917 में आपने नौकरी से त्यागपत्र देकर भौतिकी का प्राध्यापक बनना स्वीकार कर लिया। 1921 में ब्रिटेन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के कांग्रेस में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु ऑक्सफोर्ड जाना हुआ। लौटते समय भूमध्य सागर के जल का नीलापन देखकर आप आश्चर्यचकित रह गए। विचार किया कि समुद्र के जल में नीलापन किस कारण से है। उपकरण लेकर आप जहाज के डेक पर आ गये और घंटों सिन्धु जल का अवलोकन-निरीक्षण और प्रयोग करते रहे। इस दौरान पूर्व में विज्ञानवेत्ताओं द्वारा खोजे गये सिद्धांत और निष्कर्ष आंखों के सामने घूमते रहे कि जल का नीलापन समुद्र के अन्दर से प्रकट हो रहा है। पर आप उनसे सहमत नहीं हो पा रहे थे। तब रमनने इस रहस्य की खोज करने का संकल्प लिया और भारत आकर आपने प्रयोगशाला में 1921 से 1927 तक शोध किया जिसकी परिणति 'रमन प्रभाव' के रूप में हुई। 'रमन प्रभाव' प्रकाश का विभिन्न माध्यमों से गुजरने पर उसमें होने वाले भिन्न-भिन्न प्रकीर्णन के कारणों का अध्ययन है। सात साल की साधना का फल 'रमन प्रभाव' पर आधारित शोध पत्र 'नेचर' पत्रिका में सर्वप्रथम छपा था। 1924 में आपको रॉयल सोसायटी ऑफ लंदन का फैलो बनाया गया। 1927 में जर्मनी ने जर्मन भाषा में भौतिकशास्त्र का बीस खंडों का एक विश्वकोश प्रकाशितकिया। इसमें वाद्य यंत्रों से सम्बंधित आठवें खंड का लेखन रमन द्वारा किया गया। यह उल्लेखनीय है कि इस विश्वकोश को तैयार करने वाले आप एकमात्र गैर जर्मन व्यक्ति थे। उनके 2000 शोध पत्र विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुए। 1948 में आपने सेवानिवृत्ति के बाद बेंगलुरु में 'रमन शोध संस्थान' की स्थापना की।

भारत सरकार ने 1954 में महान कर्मयोगी विज्ञानी रमन के योगदान और वैज्ञानिक उपलब्धियों का वंदन करते हुए 'भारत रत्न' पुरस्कार प्रदान किया। रूस ने 1957 में 'लेनिन शन्ति पुरस्कार' भेंटकर सम्मानित किया। संचार मंत्रालय ने 20 पैसे का एक टिकट जारी कर आपकी स्मृति को अक्षुण्ण बना दिया। विश्व का यह महान भौतिकविद् 21 नवम्बर, 1970 को अपना लौकिक जीवन पूर्ण कर हमें अकेला छोड़ अंतिम यात्रा पर प्रस्थान कर गया। लेकिन जब तक दुनिया में भौतिकी का अध्ययन होता रहेगा, तब तक 'रमन प्रभाव' अमर रहेगा और चन्द्रशेखर वेंकट रमन भी कोटि उरों में जीवित एवं श्रद्धास्पद बने रहेंगे।

विकास और कर्ज

कृष्णार्जुन बर्वे

लेखक आजीविका मिशन से जुड़े हुए हैं।

क्या अंतिम व्यक्ति केंद्र में है?

औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत हजारों श्रमिक – विशेषकर छोटे एवं मध्यम कारखानों में काम करने वाले – नियमित सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं। अनेक श्रमिकों को न तो भविष्य निधि (PF) की निरंतर सुविधा मिलती है, न ही ईएसआई (ESI) का समुचित लाभ। अस्थायी अनुबंध, न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान और अनिश्चित रोजगार की स्थिति आज भी आम है। जब ये श्रमिक वृद्धावस्था में पहुँचते हैं, तो उनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं होता। ऐसे में सीमित पेंशन और बढ़ती महंगाई का दोहरा दबाव उनकी स्थिति को और कठिन बना देता है। आज कई योजनाएँ 'गरीबों के लिए' घोषित की जाती हैं, पर उनका स्वरूप अक्सर 'गरीबों जैसी योजना' बनकर रह जाता है। सहायता की राशि इतनी सीमित होती है कि वह सम्मानजनक जीवन का आधार नहीं, बल्कि केवल प्रतीकात्मक सहारा बनती है। यदि योजनाएँ सचमुच गरीबों के लिए हैं, तो उन्हें गरीबों जैसी नहीं, बल्कि महंगाई के अनुरूप और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने वाली योजनाएँ होना चाहिए – जहाँ सहायता नहीं, अवसर और सुरक्षा केंद्र में हों।

हम सब लाड़ली बहन योजना को भली-भांति जानते हैं। प्रदेश में 'लाड़ली बहना योजना' के माध्यम से लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को प्रतिमाह रू. 1,500 तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जाता है। निस्संदेह, जब रू. 1,500 प्रतिमाह सीधे महिला के खाते में आते हैं तो उसकी आर्थिक पहचान मजबूत होती है, परिवार में उसकी बात कुछ अधिक सुनी जाती है और बैंकिंग व्यवस्था से उसका जुड़ाव बढ़ता है। परंतु क्या केवल रू. 1,500 की मासिक सहायता ही सशक्तिकरण की परिभाषा है? क्या आर्थिक आत्मनिर्भरता का अर्थ नियमित रोजगार, कौशल विकास और दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा नहीं होना चाहिए? यदि सशक्तिकरण का अर्थ केवल नकद हस्तांतरण तक सीमित रह जाए, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम महिलाओं को वास्तव में सक्षम बना रहे हैं – या उन्हें सीमित आर्थिक सहारा देकर संतुष्ट मान रहे हैं? कागजों और घोषणाओं में योजनाएँ भले ही सशक्तिकरण का बड़ा चित्र प्रस्तुत करती हों, पर जमीन स्तर पर हालात अब भी चिंताजनक दिखाई देते हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को समय पर राशि नहीं मिलती, बैंकिंग प्रक्रियाओं में तकनीकी अड़चनें आती हैं, और पात्रता सत्यापन की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं।

दूसरी ओर, वृद्धा और विधवा पेंशन आज भी लगभग रू. 600 प्रतिमाह तक सीमित है। यह राशि वर्षों से लगभग स्थिर बनी हुई है। 60 वर्ष से अधिक आयु की वे महिलाएँ, जो केवल पेंशन पर निर्भर हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखा जाए। खुदरा महंगाई दर भले ही कुछ महीनों में नियंत्रित दिखाई दे, पर खाद्य पदार्थों, दाल, तेल, दूध, रसोई गैस, दवाइयों और परिवहन की लागत में लगातार उतार-चढ़ाव आम परिवार की जेब पर सीधा असर डालता है। निम्न आय वर्ग की आय का बड़ा हिस्सा भोजन और आवश्यक वस्तुओं पर खर्च होता है। जब आय स्थिर रहे और खर्च बढ़ता जाए, तो वास्तविक आय घटती जाती है। रू. 600 की पेंशन आज उतनी वस्तुएँ नहीं खरीद सकती, जितनी कुछ वर्ष पहले खरीद पाती थी। यही स्थिति रू. 1,500 की सहायता राशि पर भी लागू होती है – महंगाई के साथ उसकी वास्तविक क्रय शक्ति धीरे-धीरे कम होती जाती है।

इसी संदर्भ में प्रदेश के असंगठित कारखाना श्रमिकों की स्थिति और भी गंभीर है। औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत हजारों श्रमिक – विशेषकर छोटे एवं मध्यम कारखानों में काम करने वाले – नियमित सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं। अनेक श्रमिकों को न तो भविष्य निधि (PF) की निरंतर सुविधा मिलती है, न ही ईएसआई (ESI) का समुचित लाभ। अस्थायी अनुबंध, न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान और अनिश्चित रोजगार की स्थिति आज भी आम है। जब ये श्रमिक वृद्धावस्था में पहुँचते हैं, तो उनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं होता। ऐसे में सीमित पेंशन और बढ़ती महंगाई का दोहरा दबाव उनकी स्थिति को और कठिन बना देता है।

आज कई योजनाएँ 'गरीबों के लिए' घोषित की जाती हैं, पर उनका स्वरूप अक्सर 'गरीबों जैसी योजना' बनकर रह जाता है। सहायता की राशि इतनी सीमित होती है कि वह सम्मानजनक जीवन का आधार नहीं, बल्कि केवल प्रतीकात्मक सहारा बनती है। यदि योजनाएँ सचमुच गरीबों के लिए हैं, तो उन्हें गरीबों जैसी नहीं, बल्कि महंगाई के अनुरूप और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने वाली योजनाएँ होना चाहिए – जहाँ सहायता नहीं, अवसर और सुरक्षा केंद्र में हों। साथ ही यह भी आवश्यक है कि चुनाव पूर्व प्रारंभ की गई योजना में निर्धारित पात्रता का जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी सत्यापन हुआ। आय सीमा, आयु सीमा, आधार-समग्र लिंकिंग और बैंक खाते की शर्तें तय की गईं, परंतु अल्प समय में हुए बड़े पैमाने के पंजीयन के बाद लाभार्थी सूची के स्वतंत्र ऑडिट और निरंतर समीक्षा की आवश्यकता स्वाभाविक है।

इधर, मध्यप्रदेश सरकार चालू वित्त वर्ष में अब तक लगभग 67,300 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण ले चुकी है। हाल ही में 5,300 करोड़ और 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण भी उठाया गया। राज्यों के लिए ऋण लेना असामान्य नहीं है – अधोसंरचना, उद्योग, वेतन-भुगतान और पूंजीगत निवेश के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। परंतु जब इतनी बड़ी उधारी के समानांतर सामाजिक सुरक्षा की वास्तविक स्थिति और महंगाई के प्रभाव पर दृष्टि डालते हैं, तो प्राथमिकताओं का प्रश्न उठना स्वाभाविक है। यदि राज्य विकास कार्यों और औद्योगिक विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर ऋण जुटाने में सक्षम है, तो उसी अनुपात में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की महंगाई के अनुरूप समीक्षा, असंगठित कारखाना श्रमिकों के लिए न्यूनतम आय सुरक्षा, और नए पात्र लाभार्थियों के पंजीयन पर भी गंभीर विचार होना चाहिए। विकास का अर्थ केवल निवेश और उद्योग नहीं, बल्कि उस उद्योग में काम करने वाले श्रमिक और वृद्ध नागरिक की आर्थिक सुरक्षा भी है। सड़कों और कारखानों के साथ-साथ आम नागरिक की सामाजिक सुरक्षा भी सुदृढ़ हो – यही संतुलित और संवेदनशील शासन की पहचान है।

राजनेता

योगेंद्र सिंह परिहार
स्वतंत्र लेखक

राजनीति के पुरोधा दिग्विजय सिंह जी, जमीनी संघर्ष और जन सेवा के पर्याय हैं

मध्यप्रदेश की ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति में उन विरले नेताओं के नामों को उंगलियों पर गिना जा सकता है जिनका जुड़ाव सीधे जमीन और आम कार्यकर्ताओं से है। इस फेहरिस्त में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वे जितने कद काठी से मजबूत हैं उतने ही बौद्धिक रूप से ज़हीन और सुलझे हुए राजनेता हैं। उनकी विलक्षण स्मरण शक्ति का तो पूरा देश कायल है। दशकों पुराने मिलने वालों को नाम से पुकारना उनकी विशिष्ट पहचान है।

दिग्विजय सिंह जी ने संपन्न व राजसी पृष्ठभूमि होने के बावजूद वैभव के स्थान पर संघर्ष को प्राथमिकता दी। उनकी राजनीति विशुद्ध जमीनी और जन सेवा को समर्पित रहती है। इसीलिए तो उन्हें जमीनी राजनीति का पुरोधा कहा जाता है। उन्होंने सत्ता और संगठन में संगठन को सर्वोपरि रखा। दिग्विजय सिंह जी ने संगठन के कार्यों में उनकी रुचि से जुड़ा एक बड़ा रोचक वाक्या सुनाया। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी जी ने पूरे देश में सक्रिय युवा नेतृत्व की खोज के लिए टैलेंट हंट का आयोजन किया था जिसकी जिम्मेदारी तरुण गोगोई जी को दी गई थी। जिसमें देश भर से युवाओं का चयन किया गया उनमें से एक वे भी थे। वे बताते हैं कि उस वक्त उनका इंटरव्यू राजीव गांधी जी ने स्वयं लिया था। राजीव जी ने इंटरव्यू के दौरान दिग्विजय सिंह जी से पूछा कि 'आप क्या करना चाहते हो तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। राजीव जी ने कहा कि मेरे साथ काम करने के लिए आपको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, तब दिग्विजय सिंह जी न कहा कि आप कहें तो मैं आज रात को भोपाल पहुंचकर इस्तीफा दे देता हूं। हालांकि राजीव जी न उनका इस्तीफा उस वक्त नहीं लिया। और बाद में राजीव गांधी जी ने उन्हें मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया।'

मध्यप्रदेश जैसे विशाल राज्य तब जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, वहां संगठन को खड़ा करना हंसी खेल नहीं था। तब दिग्विजय सिंह जी ने एक गाड़ी में बोरिया बिस्तर बांधकर पूरे प्रदेश को नाप दिया था। गांव-गांव रात रुक कर लोगों के मिजाज को समझा। ब्लॉक स्तर पर जाकर अच्छे लोगों को ढूंढकर पदों पर बैठाया। जमीन पर इतना काम किया कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस दिखाई देने लगी। उन्होंने प्रदेश की तासीर को समझा, विधानसभा चुनाव लड़ने लायक नेताओं को तैयार किया। परिणाम स्वरूप 1993 में मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी।

ताज्जुब ये था कि 1993 में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले किसी ने दिग्विजय सिंह जी के मुख से मुख्यमंत्री बनने की बात तक नहीं सुनी थी। क्योंकि उन्होंने इस बात का कभी शोर नहीं मचाया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है बल्कि जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने एकाग्रता के साथ चिड़िया की आंख को भेदने का लक्ष्य बनाया था उसी तरह दिग्विजय सिंह जी ने मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का एकमेव लक्ष्य तय कर रखा था। अपने संकल्प के प्रति गंभीरता के साथ दृढ़ प्रतिज्ञ रहने की वजह से ही उन्होंने सरकार बनाने के लक्ष्य को पूरा किया था।

दिग्विजय सिंह जी में अपार संगठन क्षमताएं हैं। वे अक्सर कहते हैं जिस पार्टी के पास कैडर, कार्यकर्ता और कार्यक्रम होंगे वो पार्टी हर परिस्थिति में सफल होगी। दिग्विजय सिंह जी राजनीति के शुरुआती दौर से ही संगठन के विभिन्न पदों पर रहे। 1971 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। 1972 में गुना जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बने। 1978 से 1980 तक मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के महामंत्री और प्रभारी बनाए गए तब भंवर सिंह पोर्ते जी प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे और दिग्विजय सिंह जी विधायक थे। वे 1985 से 1988 तक एवं 1991 से 1994 तक मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 2004 के बाद लगभग 13 साल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे। उसी दौरान वे कई राज्यों के संगठन प्रभारी भी थे। यही कारण है कि संगठन के छोटे से बड़े पदों पर रहने की वजह से वे संगठन की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। संगठन को मजबूत करने का उनका हमेशा एक ही फार्मूला रहा, संगठन को स्वायत्त बनाना और उसका विकेंद्रीकरण किया जाना। वे विकेंद्रीकरण के इतने बड़े हिमायती थे कि जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने राजीव गांधी

जी के सपने को साकार करते हुए ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण कर त्रि- स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की।

दिग्विजय सिंह जी ने जन-मानस की नब्ज समझने के लिए महात्मा गांधी जी की तरह हमेशा 'पदयात्रा' को ही अपना सबसे अचूक अस्त्र बनाया। इसका सबसे अनुपम उदाहरण उनकी 'नर्मदा परिक्रमा' रही, जहाँ उन्होंने 3,300 किलोमीटर की कठिन दूरी पैदल तय कर अपनी अटूट आस्था और अदम्य इच्छाशक्ति का परिचय दिया। हालांकि यह उनकी पूर्णतः एक आध्यात्मिक और निजी साधना थी, किंतु इस कठिन तपस्या के दौरान अनगिनत गांवों और मजरों से गुजरते हुए उन्होंने जो जन-संवाद किया, उसने प्रदेश की जनता के मन में उनके प्रति अगाध विश्वास भर दिया। जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। विनम्रता के साथ यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि दिग्विजय सिंह जी की 'पैदल नर्मदा परिक्रमा' रूपी मंथन से अमृत के रूप में जनता और कांग्रेस नेताओं के बीच में आत्मिक जुड़ाव उभर कर सामने आया और फिर जन-आशीर्वाद ने 2018 में मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी की राह प्रशस्त की।

दिग्विजय सिंह जी की धार्मिक पदयात्रा के अनुभव का लाभ देश ने तब भी देखा, जब राहुल गांधी जी की 'भारत जोड़ो यात्रा' के प्रबंधन व संचालन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। उस एक पदयात्रा ने राहुल गांधी जी और कांग्रेस का कायापलट कर दिया। लोगों ने पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी जी को करीब से देखा तब उन्हें पता लगा कि राहुल जी के बारे में उन्हें झूठ बताया जाता रहा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा राहुल गांधी जी को गलत ठहराने का एक षड्यंत्र रचा गया, जबकि वास्तविकता तो कुछ और ही है। भारत जोड़ो यात्रा से ही राहुल गांधी जी की छवि और निखरकर सामने आई। ऐसी ऐतिहासिक यात्रा को सुचारु रूप से चलाने की ज़िम्मेदारी दिग्विजय सिंह जी ने बखूबी निभाई। नर्मदा तट की पगडंडियों से लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की सड़कों तक, दिग्विजय सिंह जी ने यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल सत्ता के गलियारों के खिलाड़ी नहीं, बल्कि जमीन पर पसीना बहाने वाले एक सच्चे वैचारिक तपस्वी हैं।

दिग्विजय सिंह जी की संगठन में पकड़ इसीलिए भी है कि वे नेताओं-कार्यकर्ताओं में समन्वय और आपसी तालमेल बनाने में माहिर हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1993 से 2003 तक 10 साल चली कांग्रेस की दिग्विजय सरकार रही। दिग्विजय सिंह जी की समन्वय शक्ति का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी दिग्गज नेताओं के बीच संतुलन बनाते हुए वे 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उस दौर में मध्यप्रदेश की राजनीति में अर्जुन सिंह जी, मोती लाल बोरा जी, माधवराव सिंधिया जी, विद्याचरण शुक्ल जी, श्यामाचरण शुक्ला जी, कमलनाथ जी, सुभाष यादव जी, श्रीमती जमुना देवी जी व शिवभानु सिंह सोलंकी जी जैसे प्रभावशाली नेताओं का अच्छा खासा वर्चस्व था और इन शीर्षस्थ नेताओं के साथ बिना तालमेल बनाए सत्ता के शिखर पर बने रहना आसान कार्य नहीं था। लेकिन दिग्विजय सिंह जी की समन्वय क्षमता ने वो करिश्मा भी कर दिखाया था।

दिग्विजय सिंह जी हर कार्यकर्ता को जमीन से जुड़े रहने के लिए पंच 'स' का अचूक नुस्खा बताते हैं। संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य और सकारात्मक सोच। यदि हर कार्यकर्ता और नेता ये नुस्खा अपना ले तो उसके बाद उन्हें सफलता हासिल न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वे यह भी बताते हैं कि नेताओं को चाहिए कि उन्हें धैर्य के साथ लोगों को सुनना भी सीखना चाहिए, यदि आपने जनता और पार्टी कार्यकर्ता की बात ध्यान से सुन ली तो काम बताने वाले को उतने में ही संतोष मिल जाता है।

संगठन की मजबूती की पैरवी करने वाले दिग्विजय सिंह जी की खास बात यही है कि वे पक्के गांधी-नेहरू वादी नेता हैं, वे कांग्रेस की हर टूट में अटूट रहे क्योंकि विचारधारा को उन्होंने हर क्षण जिया। वे दिल से ये बात मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें खूब दिया, इसीलिए पार्टी के खिलाफ बगावत करने के बारे में वे सपने में भी नहीं सोच सकते। हां, सांगठनिक स्तर पर सुधार की बात वे करते रहते हैं पहले भी करते थे और अपने मातृ संगठन की भलाई के लिए हमेशा करते रहेंगे जिसमें किसी को व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए और न बुरा मानना चाहिए।

28 फरवरी को कांग्रेस संगठन की रीढ़, कार्यकर्ताओं के अभिभावक एवं जन-जन के लाडले जनप्रतिनिधि राज्यसभा सांसद एवं मध्यप्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का जन्मदिवस है। हम उन्हें जन्मदिवस पर ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ और सफल व सक्रिय दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं।

इस युग में मां नर्मदा ही साक्षात हैं, जैविक खेती कृषि उन्नति के आवश्यक है, युवाओं को सात्विक बनना जरूरी दादा गुरु

सोहागपुर । निराहार समर्थ दादा गुरु सोहागपुर ब्लाक में समीपवर्ती नर्मदा नदी के विभिन्न घाटों एवं ग्रामों होकर माखननगर ब्लाक में नर्मदा नदी घाटों से होकर ग्राम सतवासा पहुंचे। यहां जिला जनपद पंचायत सदस्य एवं वरिष्ठ पत्रकार हाकमसिंह पटेल भोपाल ने दादा गुरु का ग्रामीणों के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर समर्थ दादा गुरु ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर दादा गुरु ने ग्रामीणों से कहा कि इस युग में मां नर्मदा ही साक्षात हैं। ग्रामों में जैविक कृषि समृद्धि एवं उन्नति के लिए आवश्यक है। आपने आह्वान किया कि किसान जैविक खेती को अपनाएं। गऊ माता की रक्षा की सेवा करेंगे तो समाज, परिवार, गांव की रक्षा अपने आप हो जाएगी। आपने युवाओं पर भी अपनी सटीक टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को शुद्ध सात्विक बनने की अहम जरूरत है। खानपान से दूषित गुमराह करने वालों को सत मार्ग पर लाना होगा। आपने अपने सारगर्भित उद्बोधन में मां नर्मदा को सर्वोच्च स्थान दिया। आपने अंत में कहा कि मां नर्मदा की परिक्रमा निरंतर रहेग तथा धर्म और प्रकृति के संरक्षण-संवर्धन के लिए मेरा पूर्ण समर्पण रहेगा। इस अवसर पर ग्राम सतवासा ही नहीं आस-पास के हजारों नागरिक एवं मातृशक्ति उपस्थित थीं। उल्लेखनीय है कि दादा गुरु निराहार रहकर लगातार नर्मदा परिक्रमा कर रहते रहते हैं। उनके साथ भारी संख्या में नागरिक एवं मातृशक्ति भी परिक्रमा में शामिल रहते हैं।

जिला नर्मदापुरम में आगामी त्यौहारों पर अधिकारियों की ड्यूटी

सोहागपुर । जिला नर्मदापुरम में आगामी त्यौहारों पर मार्च माह में आयोजित होने वाले प्रमुख त्यौहार, 02 मार्च स्नान पर्व, 03 मार्च, होलिका दहन, स्नान दान, वृत पूर्णिमा, 03 मार्च घुरेंडी (होली उत्सव), 04 मार्च बसंत उत्सव, 08 मार्च रंगपंचमी, 18 मार्च चैत्र अमावस्या, 19 मार्च चैत्र नवरात्र प्रारंभ, गुडी पड़वा, 20 मार्च झूलेलाल जयंती, चैती चांद, 21 मार्च ईद-उल-फित्तर, 27 मार्च रामनवमी, श्री दुर्गा नवमी एवं 31 मार्च महावीर जयंती के अवसर पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम राजीव रंजन पाण्डे ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं अधिकारियों की ड्यूटियां निर्धारित की हैं।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम श्री पाण्डे ने सुश्री प्रियंका भल्लावी को सोहागपुर, आकिप खान (आईएएस) अनुविभागीय दण्डाधिकारी पिपरिया, नीलेश शर्मा अनुविभागीय दण्डाधिकारी इटारसी, विजय राय अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिवनी मालवा, जय सोलंकी अनुविभागीय दण्डाधिकारी नर्मदापुरम एवं देवेन्द्र प्रताप सिंह सिटी मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम की ड्यूटी लगाकर अपने-अपने अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले घाट स्थलों पर कार्यपालिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रभारी अधिकारी का दायित्व सौंपा है।

शंकरलालजी राठौर का देहांत होने पर राठौर परिवार द्वारा धार शहर का 32वां नेत्रदान

धार। धार के दौलत नगर निवासी 72 वर्षीय श्री शंकरलालजी राठौर का 26 फरवरी को उपचार के दौरान देहांत हो गया था। दुख की इस घड़ी में उनके पुत्र सुनील, अनिल, योगेश एवं उनके अन्य परिवार जनों ने उनके नेत्रदान का निर्णय किया। इस हेतु धार मानव सेवा कल्याण सेवा समिति से सम्पर्क किया गया। समिति द्वारा भोज हॉस्पिटल के नेत्र विभाग के डॉ. सौरभ बौरासी और उनकी सहायिका पूर्णिमा के सहयोग से उनके नेत्रदान की प्रक्रिया अल्प समय में पूर्ण की। इस नेत्रदान से 2 से 4 लोगों को आँखों में रोशनी प्राप्त होगी जो कि मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ही पुण्य का कार्य है। समिति द्वारा धार नगर में किया गया यह 32वां नेत्रदान है। इस नेत्रदान हेतु समिति द्वारा राठौर परिवार का आभार व्यक्त किया गया और नेत्रदानी श्री शंकरलालजी राठौर को श्रद्धांजलि दी गई।

अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ पिता करता था दुष्कर्म

● बेटी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार

कलयुगी पिता ने हवालात में किया आत्महत्या का प्रयास

बैतूल। मुलताई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 10 वर्षीय नाबालिग बालिका ने अपने ही पिता पर लंबे समय से अनुचित कृत्य (दुष्कर्म) करने, डराने धमकाने एवं जान से खत्म करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पिता ने पुलिस लॉकअप में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। आरोपी की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे बैतूल जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। जहां से उसे एम्स भोपाल रेफर किए जाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 26 फरवरी को डायल 112 पर नाबालिग बालिका की मां ने सूचना दी गई कि उसके पति द्वारा उसकी 10 वर्षीय बेटी को कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया जा रहा है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डायल 112 तत्काल मौके पर पहुँची और कमरे को खुलवाकर पीड़िता को पिता से चंगुल से मुक्त कराया और आरोपी को मुलताई थाना लेकर आए। डायल 112

के साथ ही नाबालिग बालिका अपनी माता के साथ थाना मुलताई आई और रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 65(2), 64(2)(एफ), 64(2)(एम), 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं 5(एल)/6, 5(एम)/6, 5(एन)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

डरा-धमकाकर करता था अनुचित कृत्य - नाबालिग बालिका ने बताया कि उसके पिता द्वारा जब-जब उसकी मां घर पर नहीं होती थी, तब-तब लंबे समय से उसके साथ अनुचित कृत्य किया जा रहा है तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती था। नाबालिग द्वारा पूर्व में अपनी मां से पिता के द्वारा किए गए अनुचित कृत्य की जानकारी देने पर आरोपी द्वारा उसकी मां को भी कई बार मारा-पीटा गया एवं धमकाया गया। नाबालिग बालिका ने पिता पर लंबे समय से दुष्कर्म करने एवं बताने पर डराने-धमकाने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। जिसकी शिकायत नाबालिग बालिका ने थाने में दर्ज कराई है।

मां ने डायल 112 से ली मदद - कलयुगी पिता द्वारा दरवाज़ा न खोलने पर पीड़िता की मां ने डायल 112 पर फोन कर उक्त संबंध में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि 26 फरवरी को भी आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ शाम 3-4 बजे के बीच उसके पुराने घर में ले जाकर दुष्कृत्य किया एवं आरोपी के सोने पर नाबालिग घर वापस आ गई। आरोपी सोकर उठा तो नाबालिग को फिर से पुराने घर में बंद कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, जिससे नाबालिका रोने लगी। उसी समय नाबालिग की मां घर पर पहुंची, तो उसने बच्ची को रोता देखकर दरवाजा खटखटाया एवं उसकी बेटी को छोड़ने को कहा। आरोपी द्वारा दरवाज़ा न खोलने पर पीड़िता की मां द्वारा डायल 112 पर फोन कर सूचना दी गई।

हवालात में किया आत्महत्या का प्रयास - बताया जा रहा है कि हिरासत में लेने के बाद मुलताई पुलिस ने आरोपी को थाने के लॉकअप में बंद कर दिया था। उसे पुलिस न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही थी और मुलताई के एसडीओपी ए.के. सिंह तथा टीआई नरेंद्र सिंह परिहार के पेशी पर जाने के कारण उनके अधीनस्थ स्टाफ द्वारा पूरी कार्रवाई करके न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही थी, इसी बीच लॉकअप में रखी कंबल को फाड कर उसका फंदा बना कर आरोपी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। आरोपी की हालत गंभीर होने पर उसे बैतूल जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, फंदे के कारण आरोपी को सांस लेने में गंभीर दिक्कत हो रही है, जिसके चलते उसे इंक्यूबेट (वेंटिलेटर सपोर्ट) दिया गया है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसे जरूरत पडने पर पुलिस द्वारा भोपाल एम्स रेफर करने की तैयारी की जा रही है। घटना के बाद से बैतूल जिला अस्पताल में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं। पुलिस इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़िता की पहचान गोपनीय रखकर आगे की कार्रवाई कर रही है।

इनका कहना है - पिता द्वारा अपनी ही बेटी के साथ दुराचार करने का मामला सामने आया है। आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया, उसने थाने के लॉकअप में कंबल को काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। आरोपी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती किया गया।

श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ कॉमर्स इंदौर, स्टडी आईक्यू के संयुक्त सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय करियर मार्गदर्शन कार्यशाला का समापन

विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित

सुबह सवेरे संवाददाता । श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ कॉमर्स इंदौर एवं स्टडी आईक्यू आईएएस इंदौर के संयुक्त सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय करियर मार्गदर्शन कार्यशाला का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिविल सेवा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु समुचित दिशा-निर्देश एवं रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना था।

कार्यशाला के दौरान सिविल सेवा परीक्षा की संरचना, चयन प्रक्रिया, अध्ययन सामग्री का चयन, समय प्रबंधन, उत्तर लेखन तकनीक एवं सफलता की प्रभावी रणनीतियों पर विस्तृत सत्र आयोजित किए गए। प्रथम दिवस पर विशेषज्ञ गौरव शर्मा एवं हरिसिंह राजपूत द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा की बारीकियों से अवगत कराया गया। द्वितीय एवं तृतीय दिवस पर सौरभ यादव एवं अंशुल तिवारी सर ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए तैयारी के व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की तथा उनके प्रश्नों का समाधान किया।

समापन सत्र में विद्यार्थियों को सहभागिता प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर स्टडी आईक्यू के मैनेजर रवि शंकर दुहौलिया एवं अंकित चौरसिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्था की ओर से निःशुल्क कोर्स उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। अंतिम दिवस पर विद्यार्थियों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा।

कायक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. परितोष अवस्थी, समस्त समिति समन्वयक प्रो. विभोर एरेन, प्रो. डॉ. राकेश उपाध्याय, बीए विभाग संयोजक प्रो. हितेश चौधरी सहित अन्य प्राध्यापकगण उपस्थित रहे।

विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए सिविल सेवा को एक सशक्त करियर विकल्प के रूप में समझा तथा विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। महाविद्यालय प्रबंधन ने भविष्य में भी स्टडी आईक्यू के सहयोग से ऐसे आयोजन निरंतर करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आभार प्रदर्शन प्रो. श्रद्धा मानधन्या द्वारा किया गया। तकनीकी सहयोग प्रो. सत्यम पंचाल द्वारा प्रदान किया गया।

विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन नगरी मांडव में घर-घर तक पहुँच रहा है माँ नर्मदा का जल

धार। ऐसी किवदंती है कि रानी रूपमती अपने महल से मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी के दर्शन किया करती थीं। आज उसी ऐतिहासिक धरा मांडव में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा हर घर तक माँ नर्मदा का स्वच्छ पेयजल पहुँचाने की दिशा में एक नई ऐतिहासिक उपलब्धि स्थापित की गई है। गौरतलब है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी इकाई इंदौर के अंतर्गत संचालन एवं संधारण अवधि के दौरान मांडव जल प्रदाय परियोजना का कुशल संचालन निरंतर जारी है। इस परियोजना के अंतर्गत धरमपुरी जल शोधन संयंत्र से दो चरणों में पानी को लिफ्ट करते हुए लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित मांडव तक पेयजल पहुँचाया जा रहा है, जिससे पर्यटन नगरी में नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

धरमपुरी स्थित 2.4 एमएलडी क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र से मांडव तक जल पहुँचाने के लिए लगभग 550 मीटर की ऊँचाई तक पानी लिफ्ट किया जाता है, जो तकनीकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने 107 करोड़ की लागत से सागौर एवं मानपुर के दो रेलवे ओवर ब्रिज जनता को किये समर्पित

आदिवासी अंचल में रेल विकास से खुलेगा प्रगति का नया द्वार

धार। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सागौर एवं मानपुर स्थित ब्रिज क्रमांक 234 ए एवं 221 ए के दो रेलवे ओवर ब्रिजों का लोकार्पण कर उन्हें जनता की सेवा में समर्पित किया गया। लगभग 107 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इन दोनों ओवर ब्रिजों का निर्माण कार्य पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सावित्री ठाकुर ने कहा कि ये ओवर ब्रिज क्षेत्र की जनता को सुरक्षित, सुगम एवं निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करेंगे। लंबे समय से क्षेत्रवासियों की यह मांग थी, जो आज पूर्ण हुई है। उन्होंने बताया कि कुछ दिवस पूर्व ही उन्होंने इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन के प्रगतिरत कार्यों का विशेष ट्रॉली में बैठकर विस्तृत निरीक्षण किया था तथा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि निर्माण कार्य समय-सीमा में एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए। आज इन ओवर ब्रिजों का लोकार्पण उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है।

केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती ठाकुर ने उपस्थित जनसमुदाय को विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों को रेलवे परिवहन की सीधी सुविधा मिलने जा रही है। रेल संपर्क प्रारंभ होने

से आदिवासी अंचल में व्यापार, शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सेवाओं के नए अवसर विकसित होंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संकल्प है कि आदिवासी अंचलों में विकास कार्य सर्वांगीण रूप से निरंतर चलते रहें। सड़क, रेल, बिजली, पानी और अन्य आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है। केंद्र सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सागौर एवं मानपुर के ये ओवर ब्रिज केवल यातायात की सुविधा नहीं, बल्कि क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक हैं। आने वाले समय में लोकसभा क्षेत्र में और भी विकास कार्यों को गति दी जाएगी, जिससे क्षेत्र समग्र प्रगति की ओर अग्रसर हो सके।

कार्यक्रम में निलेश भारती, रेलवे डीआरएम अश्विनी कुमार सहित समस्त क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, आमजन एवं कार्यकर्ता बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

स्क्रीनिंग शिविर हंडिया में दिव्यांगजनों की स्क्रीनिंग की गई

हरदा (निप्र)। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित सभी पेंशन योजनाओं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत सभी पात्र हितग्राहियों के पेंशन फार्म तैयार कर पेंशन स्वीकृत करने एवं उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार दिव्यांग बच्चों के दिव्यांग प्रमाण पत्र तैयार करने हेतु जिले में स्क्रीनिंग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग श्री कमलेश सिंह ने बताया कि बुधवार को दिव्यांगजनों के चिन्हांकन एवं दिव्यांग प्रमाण-पत्र तैयार कराने हेतु स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के अधिकारी विशेषज्ञों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों से 151, शिविर स्थल पर 161 एवं विद्यालय में 154 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान दिव्यांगजनों को पात्रता अनुसार पेंशन एवं अन्य विभागीय योजनाओं का लाभ प्रदाय किया गया।

मदिरा के अवैध विक्रय व संग्रहण के विरूद्ध 8 प्रकरण दर्ज

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के निर्देशन व जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील भोजने के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के मंगलवार को मदिरा के अवैध विक्रय, परिवहन व संग्रहण के विरूद्ध कार्यवाही की गई। जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील भोजने ने बताया कि इस दौरान आबकारी विभाग के दल ने वृत टिमरनी के ग्राम इकडालिया, गोगिया, कामलिया ढाबा, शीतल ढाबा, राजपूत ढाबा, करताना, छीपानेर व गोंदागांव में दबिश दी। दबिश के दौरान कुल 18 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब, 21 पाव देशी शराब एवं 560 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कुल 8 प्रकरण दर्ज किये। जप्त मुद्देमाल का अनुमानित बाजार मूल्य 61175 रूपये है।

पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम में भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई विकास कार्यालय इंदौर द्वारा जिला प्रशासन नर्मदापुरम के सहयोग से पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शासकीय संभागीय आईटीआई नर्मदापुरम में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थितजनों को उद्यमिता, वित्तीय सहायता, ई-कॉमर्स, शासकीय योजनाओं, कौशल विकास, मार्केटिंग, लोन प्रोसेस संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। भारतीय डाक द्वारा डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने हेतु क्यूआर कोड लाभार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। कार्यक्रम में एमएसएमई इंदौर से सहायक निदेशक श्री गौरव गोयल एवं श्री विकास, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्रबंधक श्री देवेंद्र रघुवंशी, अग्रणी जिला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से श्री रमेश वाघेलिया, भारतीय डाक विभाग से श्री प्रदीप कुमार एवं श्री तिर्की, शासकीय संभागीय आईटीआई नर्मदापुरम से प्राचार्य संजय टेकाम, हथकरघा विभाग से दिव्या धागले, एनएसडीसी से श्री जिनेन्द्र, एमपीआईडीसी से श्री शुभम गुप्ता एवं ट्रेनिंग संस्थान सीएफटीआई से श्री सौरभ श्रीवास्तव सहित करीबन 180 हितग्राहियों ने भाग लिया। समस्त अधिकारियों ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम की विस्तृत जानकारी दी और विभिन्न समस्याओं का समाधान भी मौके पर किया।

मेहनत और संकल्प से बदली जिंदगी: खुशी आजीविका समूह से जुड़कर श्रीमती चम्पा कुशवाहा बनीं आत्मनिर्भर

नर्मदापुरम (निप्र)। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिले के विकासखंड सिवनीमालवा, ग्राम नंदरवाड़ा में संचालित 'खुशी आजीविका समूह' की सदस्य श्रीमती चम्पा कुशवाहा ने आजीविका मिशन से जुड़कर आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की प्रेरक मिसाल पेश की है। चम्पा कुशवाहा ने अपने जीवन की शुरुआत अनेक आर्थिक चुनौतियों के बीच की। परिवार की आजीविका चलाने के लिए वे मजदूरी करती थीं, जिससे उन्हें प्रतिमाह लगभग 1,000 से 2,000 रुपये तक की आय ही हो पाती थी। वर्ष 2017 में ग्राम में गठित स्व-सहायता समूहों की जानकारी मिलने पर मिशनकर्मियों एवं ग्राम की महिलाओं के प्रोत्साहन से उन्होंने 'खुशी आजीविका समूह' से जुड़ने का निर्णय लिया। समूह से जुड़ने के पश्चात उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने आटा चक्की का व्यवसाय प्रारंभ किया। इस उद्यम से उनकी मासिक आय 5,000 से 7,000 रुपये तक पहुंच गई। आगे बढ़ते हुए चम्पा ने किराना दुकान एवं गल्ला खरीदी का कार्य भी शुरू किया। उनकी मेहनत और लगन से व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हुई और आय के नए स्त्रोत विकसित हुए। वर्तमान में चम्पा कुशवाहा को आटा चक्की एवं किराना दुकान से नियमित आय प्राप्त हो रही है, साथ ही गल्ला खरीदी से अतिरिक्त लाभ भी मिल रहा है।

विदिशा जिले में नरवाई प्रबंधन की विशेष पहल

जागरूकता, तकनीक और समन्वय से बना मॉडल जिला

विदिशा (निप्र)। मध्यप्रदेश का विदिशा जिला वर्ष 2026 में नरवाई प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष पहल करते हुए एक मॉडल के रूप में उभर रहा है। रबी फसल कटाई के बाद नरवाई जलाने की समस्या के समाधान हेतु जिला प्रशासन, कृषि विभाग और किसानों के संयुक्त प्रयासों से व्यापक कार्ययोजना लागू की गई है, जिसमें जागरूकता, आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता और तकनीकी संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया गया है।

जेएफएस पोर्टल से हजारों किसानों को मिली सुविधा

जिले में जेएफएस (जस्ट फार्म सर्विस) पोर्टल के माध्यम से नरवाई प्रबंधन को गति मिली है। जिले में 113 कस्टम हायरिंग सेंटर पोर्टल से जुड़े हुए हैं, जिनमें 9854 से अधिक यंत्र प्रदाता और 1 लाख 4 हजार से अधिक किसान पंजीकृत हैं। पोर्टल के माध्यम से अब तक 11 हजार 470 एकड़ से अधिक क्षेत्र में कृषि यंत्रों द्वारा सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

इस पोर्टल पर हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रीपर, रोटावेटर, थ्रेशर और हार्वेस्टर सहित कुल 2564 कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, जिससे किसानों को नरवाई जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।

कृषि यंत्रों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान : विदिशा जिले में वर्तमान में 528 से अधिक कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, जबकि वर्ष 2025-26 में 1435 नए यंत्रों का लक्ष्य रखा गया है। इनमें प्रमुख रूप से रू-153 सुपर सीडर एवं हैप्पी सीडर, 131 रोटावेटर, 997 हार्वेस्टर, 73 जीरो टिल सीड ड्रिल, 52 मल्चर, इन यंत्रों के माध्यम से 2476 से अधिक किसानों द्वारा नरवाई प्रबंधन किया जा चुका है।

जागरूकता अभियान से बदल रही किसानों की सोच : विदिशा जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए ग्राम स्तर पर लगातार बैठकें, प्रशिक्षण और प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। अब तक 153 सुपर सीडर एवं हैप्पी सीडर का वितरण किया जा चुका है। 997 हार्वेस्टर उपलब्ध कराए गए हैं। 48 एफपीओ और कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं। इन प्रयासों से किसानों में नरवाई न जलाने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक लाभ : नरवाई प्रबंधन से जहां पर्यावरण प्रदूषण में कमी आई है, वहीं किसानों को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। नरवाई को मिट्टी में मिलाने से, मिट्टी की उर्वरता बढ़ रही है। उर्वरकों की लागत कम हो रही है। उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही नरवाई से चारा और अन्य उपयोग भी संभव हो रहे हैं।

प्रशासन की सतत निगरानी और समन्वय : जिला प्रशासन द्वारा नरवाई प्रबंधन के लिए सतत निगरानी की जा रही है। कृषि विभाग, पंचायत विभाग और राजस्व विभाग मिलकर इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं।

विदिशा बन रहा नरवाई प्रबंधन का आदर्श : विदिशा जिले में नरवाई प्रबंधन को लेकर किए जा रहे प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय हैं। आधुनिक तकनीक, पर्याप्त संसाधन और किसानों की बढ़ती जागरूकता से यह अभियान सफल हो रहा है।

यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित हो रही है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर महिला आईटीआई में भाषण एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन

बैतूल (निप्र)। शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, मध्यवर्ती क्षेत्र (भारत सरकार परमाणु उर्जा विभाग) के तत्वावधान में 'वुमेन इन साइंस विकसीत भारत' विषय पर क्विज एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में वैज्ञानिक सोच, नवाचार की भावना तथा राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम परमाणु उर्जा विभाग के वैज्ञानिक अधिकारी श्री विजय कुमार, श्री प्रकाश बेदिया, श्री प्रकाश मुखर्जी, श्री स्मृतिरंजन साहू, श्री सतीश चैन्नमशेट्टी एवं संस्था प्राचार्य श्री अजीश पन्द्रे एवं वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी श्री रेवाशंकर पंडाग्रे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। संस्था प्राचार्य श्री अजीश पन्द्रे ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वैज्ञानिक अधिकारी श्री विजय कुमार ने छात्राओं को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने, अनुसंधान एवं नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने तथा आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने बताया कि आज महिलाएं परमाणु विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही है। श्री प्रकाश बेदिया ने बताया कि आज महिलाएं वैज्ञानिक प्रोफेसर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं रिसर्च हेड के रूप में नेतृत्व कर रही है। चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, चाहे मिसाइल या रक्षा विज्ञान हो, चाहे चिकित्सा एवं जैव प्रोद्योगिकी का क्षेत्र हो महिलाओं की सक्रिय भूमिका बढ़ते जा रही है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने वसीम खान का जीवन बदला, 10 लाख के ऋण से शुरू की वैल्डिंग वर्कशॉप

विदिशा (निप्र)। भारत सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर स्वयं का व्यवसाय शुरू करने व आत्मनिर्भर बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन विदिशा जिले में सुव्यवस्थित रूप से संचालित है, जिससे लटेरी तहसील के श्री वसीम खान लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने इस योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया और 10 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर अपना वर्कशॉप प्रारंभ किया। उनकी वर्कशॉप में तैयार सामग्री वह विदिशा सहित अन्य पांच जिलों में सप्लाई करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं, श्री वसीम का मानना है कि इस योजना ने उनका जीवन में बड़े बदलाव किए हैं।

विदिशा जिले के लटेरी तहसील के श्री वसीम खान बताते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में अपने क्षेत्र के जनपद कार्यालय से जानकारी प्राप्त की थी। फिर उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रशिक्षण आईटीआई विदिशा से लॉक स्मिथ जॉब रोल में प्राप्त किया, योजना के तहत उन्होंने 10,00000 दस लाख रुपए की ऋण राशि प्राप्त की। जिसमें उन्होंने लटेरी में अपना वेल्डिंग वर्क शॉप प्रारंभ किया और आज वह मध्य प्रदेश के लगभग 5 जिलों में अपनी वर्कशॉप में तैयार सामग्री सप्लाई कर रहे हैं। वह कहते हैं कि इस योजना ने उनका जीवन बदल दिया है और आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति करने में सहायता प्रदान की है।

फ्लोरोसिसि से बचाव हेतु लोगों को जागरूक करने तथा पेयजल स्त्रोतों की नियमित जांच के कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने दिए निर्देश

रायसेन (निप्र)। राष्ट्रीय फ्लोरोसिसि निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय को-आर्डीनेशन बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित वीसी कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने चिकित्सा अधिकारियों से जिले में फ्लोरोसिस से बचाव हेतु जागरूकता गतिविधियों, फ्लोरोसिस से प्रभावित मरीजों की जांच और उपचार संबंधी जानकारी लेते हुए दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही फ्लोरोसिस के प्रति जागरूकता लाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने तथा पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री को जिले में नियमित रूप से नलकूपों, ट्यूबवेल के पानी की जांच किए जाने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल के नमूनों की नियमित जांच करने और असुरक्षित स्त्रोतों को चिन्हित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लोराइड मुक्त, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही फ्लोरोसिस से बचाव के लिए नागरिकों को फ्लोराइड युक्त पानी के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जाए। इसके साथ ही फ्लोरोसिस से प्रभावित मरीजों का समुचित उपचार किया जाए तथा सतत् मॉनीटरिंग भी की जाए। बैठक में प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि जिले में करीब 354 ग्राम फ्लोराइड से प्रभावित हैं, इनमें विकासखण्ड गैरतगंज के 88, सिलवानी के 93, बेगमगंज के 107, बरेली के 30, उदयपुरा के 20, सांची के 10 और औबेदुल्लागंज के 02 ग्राम फ्लोराइड से प्रभावित है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगभग 106 ग्रामों में भ्रमण कर बच्चों तथा ग्रामीणों का परीक्षण किया गया। इनमें 3493 बच्चों का परीक्षण किया गया जिनमें लगभग 1114 बच्चे संभावित डेंटल फ्लोरोसिस से प्रभावित पाए गए। जांच उपरांत 393 बच्चों में फ्लोरोसिस की पुष्टि हुई है तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा चिन्हित किए गए प्रभावितों को कैल्सियम एवं विटामिन सी की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सतत् मॉनीटरिंग भी की जा रही है। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने निर्देशित किया कि जिले में आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पानी की जांच हेतु प्रशिक्षण दिया जाए तथा फील्ड टेस्टिंग किट वितरित की जाए। बैठक में पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री गिरीश कामले, महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश जैन, सिविल सर्जन श्री यशपाल सिंह बाल्यान, जिला फ्लोरोसिसि कंसल्टेंट एवं नोडल अधिकारी श्री एमडी भारती सहित स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी, बीएमओ तथा बीपीएम उपस्थित रहे।

मिशन प्रबंधन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत

उद्यानिकी विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेमीनार एवं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ

नर्मदापुरम (निप्र)। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (स्ॿष्ठद्ब॥) योजना के घटक मिशन प्रबंधन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत लगभग सात सौ कृषकों का उद्यानिकी विभाग द्वारा दो दिवसीय जिला स्तरीय सेमीनार एवं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन एम पी एग्रो फार्म माखननगर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद श्री दर्शनसिंह चौधरी ने किया। कार्यक्रम में म.प्र. तैराकी संघ के अध्यक्ष श्री पीयूष शर्मा, श्री अजीत मण्डलोई सभापति जिला कृषि स्थायी समिति जिला पंचायत नर्मदापुरम, श्रीमति सावित्री बाई परनामे जनपद अध्यक्ष माखननगर, श्री निखलेश चतुर्वेदी, श्री योगेन्द्र सिंह राजपुत, श्री विपिन यादव, श्री कुवर सिंह यादव, श्री मनीष चतुर्वेदी, आदि जनप्रतिनिधी गण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में उप संचालक उद्यान श्रीमती रीता उइके द्वारा जिले में संचालित विभागीय योजनाओं सब्जी, मसाला, पुष्प, फल, मखाना, माईक्रो स्टीगेशन, क्क्स्नरूध्न आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला स्तरीय सेमीनार के प्रथम दिवस सेमीनार में मखाना की खेती, हाईटेक हार्टिकल्चर, जैविक खेती, पॉली हाउस में सब्जी/फूल उत्पादन, प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केन्द्र छिंदवाड़ा के श्री आर एल राउत, कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा के वैज्ञानिक डॉ. विजय अग्रवाल, जिला रिसोर्स पर्सन श्री सुमन्त निवारे, सुश्री विजयालक्ष्मी ने कृषकों को जानकारी दी।

सांसद श्री चौधरी ने सृष्टि हार्टिकल्चर के बागवानी से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया और उपस्थित कृषकों को खेती से संबंधित शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी कृषकों को उद्यानिकी विभाग की संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से संबोधित किया। एम पी एग्रो में मखाना प्रदर्शन प्लाट, उद्यानिकी विभाग के स्टाल, पुष्प प्रदर्शनी सृष्टि हार्टिकल्चर, आजीविका मिशन, माईक्रो इरीगेशन अंतर्गत विभिन्न संस्थाओ, क्क्स्नरूध्न के उत्पादो के स्टाल कार्यक्रम में लगाये गये जिनका अतिथिगणो एवं कृषको द्वारा अवलोकन किया गया।

जिला स्तरीय कार्यक्रम संचालन श्रीमति आरती चौरे, श्री के के रघुवंशी एवं सुश्री विजयालक्ष्मी बलवर्डे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उद्यानिकी विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी, एम पी एको माखननगर, आजीविका मिशन के अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य जिलो छिंदवाड़ा सिवनी, बालाघाट, रायसेन के कृषक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन एवं आभार प्रदर्शन श्रीमति रीता उईके उप संचालक उद्यान नर्मदापुरम द्वारा किया गया।

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर कार्यालय के रेवा सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के दिशा-निर्देशन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता सीईओ जिला पंचायत श्री हिमांशु जैन ने की।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरसिंह गेहलोत, डीएचओ डॉ. सृजन सेंगर, सिविल सर्जन डॉ. सुनीता कामले, डॉ. सुनीता नागेश, आरएमओ श्री गजेंद्र यादव, जिला परियोजना अधिकारी श्री ललित डेहरिया, जिला मीडिया प्रभारी श्री सुनील साहू, डीपीएम सुश्री कविता भोई सहित समस्त सीबीएमओ, बीएमओ, सीडीपीओ, बीईई, बीपीएम तथा स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सीईओ श्री जैन ने स्वास्थ्य विभाग के 22 प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांकों की गहन समीक्षा की। इनमें गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन एवं चार अनिवार्य जांच, एनीमिक गर्भवती महिलाओं का समुचित प्रबंधन, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, नवजात शिशुओं की गृह भेंट, पूर्ण टीकाकरण, असंचारी रोगों की स्क्रीनिंग, टीबी जांच, सिकल सेल अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन तथा स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता शामिल रहे। उन्होंने विकासखंडवार प्रगति की समीक्षा करते हुए कम प्रगति वाले विकासखंडों को 15 दिवस के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए। लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी बैठक में कार्य में लापरवाही बरतने वाले एएनएम, सीएचओ, आशा कार्यकर्ता एवं संबंधित मॉनिटरिंग अधिकारियों के विरुद्ध सेवा समाप्ति अथवा निलंबन की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश सीएमएचओ को दिए गए। साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण सहित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई तथा इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। सीईओ जिला पंचायत के निर्देशानुसार श्रम विभाग की प्रतिनिधि सुश्री सरिता साहू द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता, मासिक अंशदान, लाभ, पंजीयन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्रदान की गई। बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्रता अनुसार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने एवं शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वित प्रयासों पर जोर दिया गया।

विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध घुमंतु वर्ग के कल्याण और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्धः राज्यमंत्री

सीहोर (निप्र)। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा है कि विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, शिक्षा एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रभावी रणनीति के साथ कार्य किया जा रहा है।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने विधानसभा के समिति कक्ष क्रमांक-6 में विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, नवाचारों और गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर सागर (बण्डा) विधायक श्री वीरेंद्र सिंह लोधी, सेंधवा विधायक श्री मोंटी सोलंकी और विभाग के संचालक श्री बुद्धेश वैद्य उपस्थित रहे।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने बताया कि विभाग द्वारा इन समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। शासन की कल्याणकारी योजनाओं के समेकित विकास के लिये प्रथम चरण में प्रदेश के 12 जिलों में 'जन अभियान परिषद' के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य करवाया जा रहा है। इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, कटनी, धार, सीहोर, विदिशा, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर एवं राजगढ़ जिले शामिल हैं।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने बताया कि राष्ट्रीय विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु समुदाय कल्याण एवं विकास बोर्ड द्वारा संचालित 'सीड' परियोजना के आवास घटक के तहत प्रदेश में 3047 पात्र हितग्राहियों की सूची स्वीकृति हेतु भेजी गई है। इसके अंतर्गत 7 जिलों के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 100 प्रतिशत अनुदान (केंद्र सरकार) दिलाने के लिए एम.ओ.यू. पर सहमति बन चुकी है।

केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय बोर्ड के माध्यम से 'सीड परियोजना' में समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है। 'बडी फॉर स्टडी' संस्था के माध्यम से विद्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग, म.प्र. लोक सेवा आयोग, एसएससी, ग्रामीण बैंक, क्लेट, जेईई, नीट और एनडीए जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वर्ष 2024-25 में इस योजना से 94 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कार्यवाही प्रचलन में है।

बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में निवासरत विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु समुदायों के परिवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल कर दिया गया है। अब अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से सुगमता से जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने शासन की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित न रहे। बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए, जिन पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने वन विभाग के विजन डाक्यूमेंट का किया विमोचन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वन विभाग द्वारा प्रकाशित विजन 2047- रीइमैजिनिग फॉरेस्ट रिसोर्सेस फॉर ए क्लाइमेट रेसिलियंट फ्यूचर पुस्तक का मुख्यमंत्री निवास में विमोचन किया। विजन@2047 राज्य में जैव विविधता समृद्ध, सामुदायिक सहभागिता आधारित वन प्रबंधन की दीर्घकालिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। प्रमुख सचिव वन श्री संदीप यादव ने बताया कि प्रदेश के वनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु-सहिष्णु तथा जैव-विविधता से समृद्ध आदर्श वनों के रूप में स्थापित करना विजन@2047 का लक्ष्य है। दृष्टि पत्र में वनों के संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। दृष्टि पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आजीविका को सुरक्षित करने में सक्षम, समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में प्रदेश के वनों का संरक्षण किया जाएगा। दृष्टि पत्र में प्रदेश के वन क्षेत्र में स्थित प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयासों को भी रेखांकित किया गया है। उन्होंने बताया कि वन विभाग का यह दृष्टि पत्र भारत के पर्यावरणीय तथा विकास लक्ष्यों में निर्णायक योगदान देगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री व्ही एन अम्बाड़े, प्रबंध संचालक राज्य वन विकास निगम श्री एच यू खान, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) श्री विभाष कुमार ठाकुर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) श्री शुभरंजन सेन, प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ श्रीमती समीता राजौरा तथा संचालक वन विहार श्री विजय कुमार इस अवसर पर उपस्थित थे।

उज्जैन के सेवा धाम आश्रम में एक साल के अंदर 17 बच्चों की मौत

हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में मांगा जवाब

उज्जैन (नप्र)। सेवा धाम आश्रम में पिछले एक साल के भीतर 17 बच्चों की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया है। साथ ही सरकार को दो सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। खास बात तो यह है कि बच्चों की मौत के मामले में महिला बाल विकास विभाग के उज्जैन के कार्यक्रम अधिकारी को यह पता नहीं है कि कितने की मौत हुई है। न यह पता है कि मौत कैसे हुई है। अब अधिकारी आश्रम के निरीक्षण करने पहुंचे थे।

सेवाधाम आश्रम में हुई है बच्चों की मौत- दरअसल, पूरा मामला उज्जैन के अंबोदिया गांव स्थित सेवाधाम आश्रम का है। यहां निराश्रित, बुजुर्ग, मानसिक और शारीरिक दिव्यांगजनों को रखा जाता है। वर्तमान में यहां ऐसे 1200 लोग हैं, जिसमें महिला, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इस आश्रम पर मौत के मामले और अन्य गड़बड़ियों को लेकर समय-समय पर सवाल खड़े होते आए हैं। ऐसा ही मामला अब फिर सामने आया है।

एक साल पहले इंदौर में हुई थी बच्चों की मौत- करीब एक साल पहले 10 बच्चों की मौत के बाद इंदौर के युगपुरुष आश्रम को बंद कर दिया गया था। बेहतर देखभाल का हवाला देकर यहां के 86 बच्चों को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया था। चौंकाने वाली बात ये है कि इन 86 बच्चों में से 17 बच्चों की जान जा चुकी है। यही नहीं, सबकी मौत का कारण भी एक ही बताया गया- सांस लेने में तकलीफ।

शवदाह गृह के रिकॉर्ड की पड़ताल से खुला मामला- यह खुलासा उज्जैन जिला अस्पताल और विद्युत शवदाह गृह के रिकॉर्ड की पड़ताल से हुआ है। गौरतलब है कि 25 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार के निर्देश पर इंदौर के युगपुरुष आश्रम को बंद किया गया था। इसकी वजह थी कि जून-जुलाई 2024 में आश्रम में हैजे से 10 बच्चों की मौत हो गई थी। युगपुरुष आश्रम बंद होने के बाद वहां रह रहे 86 विशेष बच्चों (34 लड़के और 52 लड़कियां) को उज्जैन भेजा गया। इनकी उम्र 5 से 23 वर्ष के बीच थी।

23 जनवरी 2025 से मौतें शुरू- शिफ्टिंग के एक माह में ही यानी 23 जनवरी 2025 से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। उज्जैन जिला अस्पताल व शवदाह गृह के रिकॉर्ड से यह खुलासा हुआ। इससे सेवा-आश्रमों में बच्चों की स्थिति, इलाज और मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। उज्जैन के इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के रिकॉर्ड में दर्ज नामों से पुष्टि होती है कि 17 की मृत्यु हो चुकी है।

हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान- वहीं, मीडिया में खबर आने के बाद यह मामला हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने संज्ञान में लिया। एमपी हाईकोर्ट ने इंदौर के युगपुरुष धाम से उज्जैन स्थित सेवाधाम आश्रम भेजे गए बच्चों की मौतों के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

दो सप्ताह में मांगा है जवाब- हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, महिला और बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त, कलेक्टर-एसपी उज्जैन, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी एवं सेवाधाम आश्रम के अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। उज्जैन सेवाधाम आश्रम की निरीक्षण रिपोर्ट आने के बाद अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।

यूनिफॉर्म-बुक खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल सकेंगे स्कूल

8 एसडीएम करेंगे कार्रवाई, कलेक्टर ने आदेश के साथ टीमें भी बनाईं

भोपाल (नप्र)। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले ही यूनिफॉर्म और बुक की खरीद-फरोख्त को लेकर भोपाल जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म-बुक को लेकर आदेश जारी किए हैं। 8 एसडीएम को जिम्मेदारी देते हुए कार्रवाई करने को कहा है।

आदेश के मुताबिक, प्राइवेट स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य पेरेंट्स पर बुक, यूनिफॉर्म समेत स्टेशनरी खरीदने पर दवाब नहीं डाल सकेंगे। वर्तमान में कई स्कूल ऐसे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को निर्धारित दुकानों से ही यूनिफॉर्म, जूते, टाई, किताबें, कॉपियां खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। नए सत्र में यह न हो, इसलिए कलेक्टर हर अनुभाग में एसडीएम समेत 5 सदस्यी टीम का गठन किया है। इसमें संबंधित एसडीएम, तहासीलदार और सरकारी स्कूल के प्राचार्यों को शामिल किया गया है।

परीक्षा के बाद अप्रैल से खुलेंगे स्कूल- अभी स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, जो मार्च में भी होंगी। इसके बाद अप्रैल में स्कूल फिर से खुलेंगे। इसी दौरान पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म, बुक्स समेत अन्य शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है। पिछले साल भी कलेक्टर सिंह ने नए शिक्षा सत्र से पहले आदेश जारी किए थे।

इन्हें बनाया जिम्मेदार

एमपी नगर एसडीएम एलके खरे के साथ तहसीलदार दीपक कुमार द्विवेदी, प्राचार्य एसके खांडेकर, वंदना शुक्ला और नूतन सक्सेना।

टीटी नगर एसडीएम अर्चना शर्मा के साथ तहसीलदार कुणाल राउत, प्राचार्य अभिषेक बैंस, सरला कश्यप और मनोज रोहतास।

कोलार एसडीएम पीसी पांडेय के साथ तहसीलदार एनएस परमार, प्राचार्य आरके यादव, शीला मौर्य और बीआरसी रूपाली रिछारिया।

शहर वृत्त एसडीएम दीपक पांडेय के साथ तहसीलदार रामप्रकाश पांडे, प्राचार्य एसके उपाध्याय, एसएस सिसौदिया और बीआरसी अमित श्रीवास्तव।

बैरागढ़ एसडीएम रविशंकर राय के साथ तहसीलदार हर्षविक्रम सिंह, प्राचार्य अनामिका खरे, नीलम बसानिया और वेरोनिका मंडल।

गोविंदपुरा एसडीएम भुवन गुप्ता के साथ तहसीलदार सौरभ वर्मा, प्राचार्य विनोद राजोरिया, स्मिता मेश्राम और चक्रेश कुमार जैन।

हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया के साथ तहसीलदार आलोक पारे, प्राचार्य सुनीता जैन, रचना श्रीवास्तव और अमिता शर्मा।

बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा के साथ तहसीलदार दिलीप चौरसिया, बीईओ आरएन श्रीवास्त्री, प्राचार्य गीता जोशी और बृजेंद्र कुमार कटारे।

शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेगी टीम

कलेक्टर ने टीम से कहा है कि किसी पेरेंट्स की जैसे ही शिकायत मिले, उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए। संबंधित स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

हार्ट-अटैक से आंखों के सामने पिता की मौत...

सीपीआर देता रहा बेटा, सीने में उठा था तेज दर्द, एम्बुलेंस नहीं मिली तो लोडर वाहन से लाया

छतरपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एम्बुलेंस न मिलने के कारण एक बुजुर्ग की जान चली गई। हार्ट अटैक की आशंका में परिजन लोडर वाहन से अस्पताल ले गए। बेटा चलती गाड़ी में रास्ते भर पिता को सीपीआर देता रहा, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम तालगांव निवासी 65 वर्षीय जगदीश विश्वकर्मा के रूप में हुई है। वे अपने बेटे संतोष विश्वकर्मा के साथ शहर आए थे। इसी दौरान ग्राम बरकोंहा के पास अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द और सांस लेने में दिक्कत होने लगी।

ट्रैफिक जाम में फंसी लोडर गाड़ी, देर से पहुंची अस्पताल- परिजन के अनुसार, मौके पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी। मजबूरी में उन्हें एक लोडर वाहन से छतरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में हालत बिगड़ती देख बेटे संतोष ने चलती गाड़ी में ही सीपीआर देने की कोशिश की।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शहर में ट्रैफिक जाम के कारण वाहन को अस्पताल पहुंचने में परेशानी हुई। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर रास्ता साफ कराया, तब जाकर लोडर अस्पताल तक पहुंच सका।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी- डॉक्टर्स ने बताया कि जब मरीज को अस्पताल लाया गया, तब उसकी हालत बहुत गंभीर थी। जांच करने पर पता चला कि उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। वहीं सिविल सर्जन ने भी कहा कि मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। शुरुआती तौर पर मौत की वजह हार्ट अटैक मानी जा रही है। हालांकि सही कारण पोस्टमॉर्टम के बाद ही पता चल सकता था, लेकिन परिजन पोस्टमॉर्टम कराए बिना ही शव को घर ले गए।

पन्ना में लुटेरी दुल्हन गिरोह के 9 लोग गिरफ्तार

शादी का झांसा देकर युवक को किया अगवा, फिर डरा-धमकाकर लूटे 1 लाख रुपए

पन्ना (नप्र)। पन्ना जिले में पुलिस ने अंतरराज्यीय लुटेरी दुल्हन गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह ने शादी का झांसा देकर न केवल लूटपाट की, बल्कि अपहरण जैसी वारदातों को भी अंजाम दिया। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। बृजपुर थाना पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह कुंवारे युवकों को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था। फिर डरा-धमकाकर या अपहरण कर उनसे मोटी रकम वसूलता था।

दो लड़कियों और एक महिला से मिलवाया

इस गिरोह का शिकार नयागांव धरमपुर निवासी 43 वर्षीय बसंत लाल त्रिपाठी बने। शादी की तलाश में उन्होंने लल्लू चौधरी नामक व्यक्ति से संपर्क किया था। योजना के तहत 23 फरवरी को त्रिपाठी पहाड़ीखेड़ा में लड़की देखने पहुंचे, जहां उन्हें दो लड़कियों और एक 1 लाख रुपए, टैबलेट लूट लिए शादी के नाम पर पैसों की मांग को लेकर विवाद हुआ।

प्रदेश सरकार के कैलेंडर पर छिड़ा इम्पाला विवाद

- **पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बोले- जो हिरण देश में ही नहीं, उसका फोटो क्यों लगाया**

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी डायरी के बाद अब सरकारी कैलेंडर भी विवादों में आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार की ओर से प्रकाशित कैलेंडर पर छपी हिरण की तस्वीर को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर कैलेंडर की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री जी! जिस हिरण का चित्र एमपी के कैलेंडर पर लगाया गया है, वह न तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है और न ही भारत में। उन्होंने दावा किया कि यह 'इम्पाला' है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। पूर्व सीएम ने पोस्ट में लिखा- सोच-समझकर करें चयन।

सियासत गरमाने के आसार

दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे को सरकार की लापरवाही से जोड़कर देख रहा है। हालांकि, इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

अब देखना होगा कि सरकार इस विवाद पर क्या स्पष्टीकरण देती है और क्या भविष्य में शासकीय प्रकाशनों में चित्रों के चयन को लेकर कोई नई प्रक्रिया अपनाई जाती है।

यह बड़ी हास्यास्पद कार्यशैली- कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई ने कहा- यह बड़ा हास्यास्पद है कि भारत में इतने वन्यप्राणी हैं। शेर-चीते हैं, जिनकी फोटो लगाई जा सकती थी, लेकिन अफसर पता नहीं कहां से फोटो खोज कर लाते हैं और कैलेंडर पर लगा देते हैं।

नकारात्मक राजनीति करती है कांग्रेस- कैलेंडर पर छपी फोटो को लेकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मूल बातों पर कांग्रेसियों का ध्यान नहीं है।

ये बड़ी त्रुटि है

कैलेंडर के मुद्दे पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मप्र वाइल्ड लाइफ के संबंध में देश में सदैव अव्वल रहा है। प्रदेश की इतनी वन संपदा के बावजूद ऐसा किया गया है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लोग जिम्मेदार हैं। सरकार के अधिकारी जमीनी स्तर पर हकीकत से कितने दूर हैं।

कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा- प्रशासन इतना निरंकुश हो गया है और अधिकारी इतने मदमस्त हो गए हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि हम क्या लिटरेचर छाप रहे हैं। उसमें कितना करोड़ खर्च होता है। उसमें हम यही नहीं समझ पाए कि हम क्या छाप रहे हैं। इतनी अराजकता का माहौल हमने 50 साल में कभी नहीं देखा।

अमृत 2.0 की खुदाई से बेहाल शहर

21 दिन में मरम्मत का नियम, दो महीने से सड़कें खुदी पड़ीं, धूल से 200 पार पीएम-10

भोपाल (नप्र)। यह तस्वीर एमपी नगर में गायत्री मंदिर से जाने वाली 80 फिट रोड की है। यहां करीब दो महीने पहले सड़क बीच से खोदी गई थी। सीवेज लाइन बिछाने के बाद गड्ढे को मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया। कमर्शियल इलाका होने से यहां वाहनों की आवाजाही अधिक है, जिससे धूल लगातार उड़ रही है।

एमपी नगर जोन-1 और 2 के अलावा शाहपुरा, गुलमोहर, त्रिलंगा, गोविंदपुरा, बागसेवनिया और अरेरा कॉलोनी,नीलबढ़ में भी खुदाई के बाद रेस्टोरेशन अधूरा है। कई जगह पानी की पाइप लाइन टूटने की समस्या भी सामने आई हैं। एमपी नगर में सीवेज का पानी जमीन में मिलने की शिकायतें भी मिली हैं।

नियमानुसार, अमृत 2.0 के तहत सीवरेज नेटवर्क के लिए खोदी गई सड़कों का ठेकेदार को 21 दिन में रेस्टोरेशन (मरम्मत) करना होता है, लेकिन कई इलाकों में दो-दो महीने से गड्ढे खुले पड़े हैं। अब तक इन सड़कों को ठीक नहीं किया गया है। इससे धूल उड़ रही है।

अरेरा हिल्स स्थित पर्यावास भवन मॉनिटरिंग सेंटर पर बीते सात दिन में से चार दिन पीएम-10 का स्तर बहुत खराब यानी 200 के पार दर्ज हुआ। यह टीटी

नगर और ईदगाह हिल्स से काफी अधिक चल रहा है। एमपी नगर सहित शहर के व्यस्त इलाकों में स्थिति ज्यादा खराब है।

इधर, नगर निगम का कहना है कि अभी मैन लाइन डाली गई है। घरों के कनेक्शन जोड़ने के लिए दोबारा खुदाई की जाएगी, इसलिए गड्ढे नहीं भरे गए। प्रोजेक्ट के तहत 984 किलोमीटर सीवर लाइन, 10 एसटीपी और 1.21 लाख से ज्यादा घरों को कनेक्शन दिए जाएंगे। इस पर तीन साल में करीब एक हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। धूल, गड्ढों और पानी की पाइपलाइन फूटने से लोग परेशान है।

चार जोन में बांटकर तैयार किए पैकेज

- **पैकेज-1** : वार्ड 4, 5, 6, 80, 81, 82, 83, 84, 85 और 26 में कुल 182 किमी सीवर लाइन डाली जाएगी।
- **पैकेज-2** : वार्ड 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72 और 74 में कुल 141 किमी सीवर नेटवर्क बिछाया जाएगा।
- **पैकेज-3** : वार्ड 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 45, 48, 49, और 51 में कुल 393 किलोमीटर सीवर नेटवर्क बिछाया जाएगा।
- **पैकेज-4** : वार्ड 58, 59, 70, 41, 40, 39, 71, 38, 36, 37, 76, 79, 78, 77, 44, 69 और 75 में नेटवर्क विस्तार होगा।
- **दूसरे पैकेज का काम भी शुरू...** पहले पैकेज के बाद अब दूसरे पैकेज का काम भी गोविंदपुरा और नरेला में शुरू हो गया है। इससे आने वाले समय में अन्य इलाकों में भी लोगों को परेशानी होगी। कई इलाकों में पानी की पाइप लाइनें भी टूट गई हैं। हालांकि टेंडर शर्त में पाइप लाइन कटने पर उसे ठीक करने की जिम्मेदारी कांट्रेक्टर की है।
- **उपाय नहीं किए तो और बढ़ेगा पीएम-10 का स्तर-** प्रदूषण में धूल प्रमुख कारण होता है। जहां निर्माण हो रहा है, उसे ग्रीन नेट से कवर करना चाहिए। अगर इलाका कवर नहीं हो सकता है, तो पानी का छिड़काव करना चाहिए। यह उपाय नहीं किए तो पीएम-10 और बढ़ेगा।

-श्रीनिवास द्विवेदी, रीजनल अधिकारी पीसीबी भोपाल

- **रेस्टोरेशन नहीं हुआ तो कांट्रेक्टर पर कार्रवाई-** एमपी नगर में सीवेज लाइन बिछाने का काम अंतिम चरण में है। अगर अब तक रेस्टोरेशन का काम नहीं हुआ है, तो कांट्रेक्टर पर कार्यवाही करेंगे।